* 19th Year
* Issue: 235
* 31.12.2025 (WEDNESDAY)
* ROURKELA
* R.N.I. No. ORIHIN/2006/18978
* (Pages-6)
* Price:2.00

e-paper-www.thekalingasamachar.com

दैनिक कलिंग समाचार

The kalingasamachar

प्रकाशक एवं संपादक : प्रकाश कुमार धल

Published From ODISHA, JHARKHAND & CHHATTISHGARH

पीएम मोदी ने 2025 को बताया नागरिक-केन्द्रित सुधारों का महावर्ष, बोले-रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार भारत

नयी दिल्ली ३०/१२ (संवाददाता): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को 2025 को भारत के लिए एक ऐतिहासिक वर्ष बताया और कहा कि देश ने कराधान, श्रम, व्यापार, ऊर्जा, शिक्षा और ग्रामीण रोजगार सहित कई क्षेत्रों में सुधारों के साथ सुधार की एक्सप्रेस में सवार हो गया है। उन्होंने कहा कि भारत ने सुधार की रफ्तार पकड़ ली है! 2025 में विभिन्न क्षेत्रों में अभूतपूर्व सुधार हुए हैं, जिन्होंने हमारी विकास यात्रा को गति प्रदान की है। ये सुधार एक विकसित भारत के निर्माण के हमारे प्रयासों को भी बल देंगे। एक विस्तृत लिंक्डइन पोस्ट में, प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि सुधारों को एक सतत राष्ट्रीय मिशन के रूप में आगे बढ़ाया गया है, जो पिछले 11 वर्षों की प्रगति पर आधारित है। उन्होंने लिखा, हमने संस्थानों का आधुनिकीकरण किया, शासन को सरल बनाया और दीर्घकालिक, समावेशी विकास की नींव को मजबूत किया।

प्रमुख उपायों में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में परिवर्तन शामिल थे, जिसमें विवादों को कम करने और अनुपालन में सुधार लाने के लिए 5त्न और 18त्न की सरल दो-स्तरीय संरचना लागू की गई। मध्यम वर्ग के करदाताओं को राहत मिली ज्योंकि 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले व्यक्तियों को आयकर नहीं देना होगा, जबकि 1961 के पुराने आयकर अधिनियम को आयकर अधिनियम, 2025 से प्रतिस्थापित कर दिया गया।

लघु और मध्यम व्यवसायों को भी लाभ हुआ ज्योंकि लघु कंपनियों की परिभाषा का विस्तार करके इसमें 100 करोड़ रुपये तक के कारोबार वाली फर्मों को शामिल किया गया, जिससे अनुपालन आसान हुआ और लागत में कमी आई। सरकार ने प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और सेवाओं में सुधार लाने के उद्देश्य से बीमा क्षेत्र में 100त्न प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी। पूंजी बाजारों में, निवेशकों की सुरक्षा को मजबूत करने, शासन व्यवस्था को बेहतर बनाने और प्रौद्योगिकी आधारित प्रणालियों के माध्यम से अनुपालन को सरल बनाने के लिए प्रतिभूति बाजार संहिता विधेयक पेश किया गया।

पांच नए समुद्री कानून पारित किए गए, जिनसे रसद व्यवस्था का आधुनिकीकरण हुआ और लागत में कमी आई। जन विश्वास पहल के तहत, अनावश्यक अपराधीकरण को समाप्त करने के लिए 71 पुराने कानूनों को निरस्त किया गया। श्रम सुधारों के तहत 29 पुराने कानूनों को चार आधुनिक श्रम संहिताओं में विलय कर दिया गया, जिससे सामाजिक सुरक्षा का विस्तार हुआ, श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा हुई और महिला कार्यबल की भागीदारी को प्रोत्साहन मिला। भारत ने न्यूजीलैंड, ओमान और ब्रिटेन के साथ व्यापार समझौते किए और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) को लागू किया, जिससे बाजार पहुंच और निवेश के अवसरों में वृद्धि हुई। परमाणु ऊर्जा का जिज्मेदारीपूर्वक विस्तार करने, निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने और देश की बढ़ती स्वच्छ ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शांति अधिनियम पेश किया गया।ग्रामीण रोजगार गारंटी को ग्राम विकास अधिनियम, 2025 के तहत 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है ताकि गांवों के बुनियादी ढांचे और आजीविका को मजबूत किया जा सके। शिक्षा के क्षेत्र में, यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई जैसे कई निकायों के स्थान पर एक एकल उच्च शिक्षा नियामक की योजना बनाई जा रही है, जिससे संस्थागत स्वायज़ाता, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।

अयोध्या में फिर होगा भव्य कार्यक्रम, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ में शामिल होंगे राजनाथ सिंह

अयोध्या ३०/१२ (संवाददाता): रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बुधवार को अयोध्या जाएंगे और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के प्रतिष्ठा द्वादशी समारोह में भाग लेंगे। सिंह ने अपने आधिकारिक एज़्स हैंडल पर एक पोस्ट साझा करते हुए इस बारे में जानकारी दी। पोस्ट में उन्होंने लिखा, कल, 31 दिसंबर को मैं अयोध्या में रहूंगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दर्शन करने और प्रतिष्ठा द्वादशी समारोह में शामिल होने के लिए उत्सुक हूं। इससे पहले, 14 दिसंबर को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने घोषणा की थी कि प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी 31 दिसंबर को मनाई जाएगी। उन्होंने बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को इस अवसर पर आमंत्रित किया गया था, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है। उन्होंने आगे कहा कि हमने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को उस दिन के लिए आमंत्रित किया है, और उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया है। जब देश के रक्षा मंत्री आते हैं, तो मुज़्यमंत्री भी आ सकते हैं। प्रतिष्ठा द्वादशी पटोत्सव के दूसरे दिन, श्री राम जन्मभूमि मंदिर में यज्ञ समारोह के अंतर्गत विभिन्न अनुष्ठान संपन्न किए गए। इनमें तत्व कलश, तत्व होम, मन्यु सूक्त होम, राम तारक मंत्र होम और अन्य पवित्र अनुष्ठान शामिल थे। शाम को, देवता की पालकी निकाली गई। पालकी प्रतिदिन तीन बार श्री राम मंदिर परिसर की परिक्रमा करती है, और यह क्रम पूरे अनुष्ठानों के दौरान जारी रहेगा। ये सभी कार्यक्रम पूज्य विश्वप्रसन्ना तीर्थ जी महाराज के मार्गदर्शन में आयोजित किए जा रहे हैं। पूजा करने वाले आचार्यों के अनुसार, यह अनुष्ठान एक वैदिक कर्मिक अनुष्ठान है जिसका उद्देश्य सृष्टि के मूलभूत तत्वों को संतुलित करना और अधर्म, बाधाओं और अशांति को दूर करना है।

अत्याचार हो रहा है...पीएम मोदी से मिलते ही ये ज़्या बोले अधीर रंजन?

३०/१२ (संवाददाता): पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही, पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और भाजपा शासित राज्यों में राज्य के प्रवासी श्रमिकों पर हो रहे अत्याचारों को लेकर चिंता व्यक्त की। दिल्ली स्थित मोदी कार्यालय में मुलाकात करने वाले चौधरी ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री से राज्य के मतुआ समुदाय के बारे में भी बात की, जो उनके अनुसार, इस बात से भयभीत है कि एसआईआर (पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव) की मतदाता सूची से उनके नाम हटा दिए जाएंगे। मोदी को लिखे अपने पत्र में चौधरी ने कहा कि पश्चिम बंगाल के प्रवासी श्रमिक, जो देश के कोने-कोने में फैले हुए हैं, विभिन्न राज्यों (विशेष रूप से भाजपा शासित राज्यों) में नियमित अंतराल पर गंभीर भेदभाव का सामना कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि ये प्रवासी श्रमिक अपनी आजीविका चलाने के लिए कड़ी मेहनत और कौशल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें देश की अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग माना जाना चाहिए। हालांकि, उन्हें हिंसा, घृणा, दुर्व्यवहार और यहां तक कि पीट-पीटकर मार डालने जैसी घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है।चौधरी ने दावा किया कि उनका एकमात्र अपराध यह है कि वे बंगाली भाषा बोलते हैं, जिसे संबंधित प्रशासन अज़्सर पड़ोसी बांग्लादेश के निवासी समझकर घुसपैठिए मान लेता है। चौधरी ने लिखा यह विडंबनापूर्ण है कि पुलिस समेत प्रशासनिक अधिकारी बांग्लाभाषी और बांग्लादेशी लोगों में कोई भेद नहीं करते। बिना कोई अपराध किए उन्हें जेल या हिरासत केंद्रों में डाल दिया जाता है, जो घोर अन्याय है। कांग्रेस नेता ने 24 दिसंबर की शाम ओडिशा के संबलपुर जिले में पीट-पीटकर मार डाले गए 19 वर्षीय प्रवासी मजदूर ज्वेल शेख के मामले का भी जिक्र किया और प्रधानमंत्री से अनुरोध किया कि वे देश की सभी राज्य सरकारों को इस तरह के भेदभाव, हिंसा और उत्पीड़न को रोकने के लिए जागरूक करें।

यात्री से मारपीट मामले पर एयर इंडिया पायलट पर बड़ी कार्रवाई, ड्यूटी से हटाया

नयी दिल्ली ३०/१२ (संवाददाता): दिल्ली पुलिस ने इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (आईजीआई) हवाई अड्डे पर एक यात्री पर हमला करने के आरोप में एअर इंडिया एज़्सप्रेस के एक 'ऑफ-ड्यूटी' पायलट को गिरफ़्तार कर लिया है। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि कैप्टन वीरेंद्र सेजवाल जांच में शामिल हुए और अधिकारी ने उनसे पूछताछ की थी। एक बयान में कहा गया, "मामला दर्ज होने के बाद जांच प्रक्रिया के दौरान, संबंधित सीसीटीवी फुटेज एकत्र किए गए और बयान दर्ज किए गए। आरोपी को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया और उसे गिरफ़्तार कर लिया गया।" सेजवाल के खिलाफ 19 दिसंबर को टर्मिनल-1 की सुरक्षा चौकी के पास हुई हिंसा के संबंध में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं 115 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 126 (गलत तरीके से रोकना) और 351 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामला 19 दिसंबर को टर्मिनल 1 की सुरक्षा जांच चौकी के पास हुई एक कथित घटना से संबंधित है, जिसमें शिकायतकर्ता अंकित दीवान ने आरोप लगाया है कि सेजवाल ने उनपर हमला किया। उस समय सेजवाल ड्यूटी पर नहीं था और एक यात्री के रूप में यात्रा कर रहा था। मिस्टर दीवान ने कहा कि उन्होंने दिल्ली पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई है और मीडिया रिपोर्ट्स से पता चला है कि स्न्ढ्ढक्र दर्ज कर ली गई है। मिस्टर दीवान ने कहा, मैं अभी अपनी सेहत पर ध्यान दे रहा हूं, और आज ष्टञ्ज स्कैन में मेरी बाईं नाक की हड्डी में डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर दिखा है। मुझे उज़्मीद है कि मुझे इस मामले में न्याय मिलेगा। दिल्ली पुलिस ने कहा, मिस्टर दीवान की ईमेल से मिली शिकायत के आधार पर, भारतीय न्याय संहिता की धारा 115 (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 126 (गलत तरीके से रोकना) और 351 के तहत मामला दर्ज किया गया है। जांच जारी है।

चाइनीज़ कहकर की गई छात्र की हत्या, अंजेल चकमा की मौत पर देशव्यापी उबाल, कार्रवाई की मांग

नयी दिल्ली ३०/१२ (संवाददाता): देहरादून में 9 दिसंबर की वह रात एक होनहार छात्र और उसके परिवार के लिए ज़िंदगी बदल देने वाली साबित हुई। एमबीए के अंतिम वर्ष का छात्र अंजेल चकमा, जो अपने करियर की नई शुरुआत के सपने देख रहा था, नस्लीय हिंसा का शिकार होकर दुनिया से चला गया।बता दें कि 24 वर्षीय अंजेल चकमा अपने छोटे भाई माइकल के साथ बाहर था, तभी कुछ युवकों ने उनसे बहस शुरू की। आरोप है कि इस दौरान उन्हें चीनी और मोमो जैसे नस्लीय शज़्द कहे गए। मौजूद जानकारी के अनुसार, जब दोनों भाइयों ने खुद को भारतीय और त्रिपुरा का निवासी बताया, तब भी हमलावर नहीं रुके। बात बढ़ी और झगड़े के दौरान अंजेल पर चाकू से हमला कर दिया गया। गंभीर रूप से घायल अंजेल को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां शुरुआत में हालत स्थिर बताई गई, लेकिन 17 दिन बाद 26 दिसंबर को उसकी मौत हो गई। इस घटना ने न सिर्फ उज़्राखंड बल्कि पूरे देश को झकझोर दिया। पुलिस के मुताबिक, इस मामले में पांच आरोपियों को गिरफ़्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, जबकि एक आरोपी अब भी फरार है। बताया जा रहा है कि आरोपी नेपाल मूल का है और उसकी तलाश के लिए पुलिस टीमें लगाई गई हैं। वहीं, परिजनों का आरोप है कि घटना के बाद एफआईआर दर्ज करने में भी देरी की गई, जिसे लेकर अब सवाल उठ रहे हैं।गौरतलब है कि अंजेल चकमा त्रिपुरा के उन युवाओं में थे जो सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े सपने देख रहे थे। उन्होंने शिक्षा ऋण लेकर उज़्राखंड में पढ़ाई की थी और एक फ्रेंच मल्टीनेशनल कंपनी में प्लेसमेंट भी हासिल कर लिया था। विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार, वह पढ़ाई के साथ-साथ खेलों में भी बेहद सक्रिय थे और फुटबॉल के अच्छे खिलाड़ी थे। इस घटना के बाद त्रिपुरा में विरोध प्रदर्शन हुए हैं। मुज़्यमंत्री माणिक साहा ने उज़्राखंड के मुज़्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात कर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है। वहीं, मेघालय के मुज़्यमंत्री कॉनराड संगमा ने भी इसे नस्लीय हिंसा बताते हुए कड़ी निंदा की है।विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा है कि यह घटना एक चेतावनी है और कैंपस में पूर्वोज़र के छात्रों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे।

खालिदा जिया के निधन पर पीएम मोदी का शोक संदेश-भारत-बांग्लादेश संबंधों में उनके योगदान को याद किया जाएगा

नयी दिल्ली ३०/१२ (संवाददाता): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और क्चहृक्क चेयरपर्सन बेगम खालिदा जिया के निधन पर शोक व्यक्त किया, जिनका ढाका में निधन हो गया। उन्होंने 2015 में उनसे हुई मुलाकात को याद किया और कहा कि उन्हें उज़्मीद है कि उनकी सोच और विरासत भारत-बांग्लादेश संबंधों को आगे भी राह दिखाती रहेगी। ङ्ग पर एक पोस्ट में मोदी ने लिखा, ढाका में पूर्व प्रधानमंत्री और क्चहृक्क चेयरपर्सन बेगम खालिदा जिया के निधन के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ। उनके परिवार और बांग्लादेश के सभी लोगों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं। ईश्वर उनके परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दे।उन्होंने आगे कहा बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री के तौर पर, बांग्लादेश के विकास के साथ-साथ भारत-बांग्लादेश संबंधों में उनके महत्वपूर्ण योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। मुझे 2015 में ढाका में उनसे हुई अपनी गर्मजोशी भरी मुलाकात याद है। हमें उज़्मीद है कि उनकी सोच और विरासत हमारी साझेदारी को आगे भी राह दिखाती रहेगी। उनकी आत्मा को शांति मिले।बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और शेख हसीना की प्रमुख राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी खालिदा जिया का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनकी राजनीतिक पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ने मंगलवार को एक बयान में यह जानकारी दी। खालिदा जिया और शेख हसीना के बीच दशकों चली प्रतिद्वंद्विता ने एक पीढ़ी तक बांग्लादेश की राजनीति को परिभाषित किया। जिया पर कई भ्रष्टाचार के मामले दर्ज थे, जिन्हें उन्होंने राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया था।

2026 में बीजेपी सरकार! अमित शाह बोले-बंगाल को घुसपैठ मुक्त कर बदलेंगे पहचान

कोलकाता ३०/१२ (संवाददाता): केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल की मुज़्यमंत्री ममता बनर्जी पर अपना हमला तेज करते हुए उन पर पड़ोसी बांग्लादेश में अशांति और घुसपैठ की बढ़ती चिंताओं के बीच सीमा पर बाड़बंदी रोकने का आरोप लगाया। ये टिप्पणियां 2026 में होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों से कुछ महीने पहले आई हैं, जिनमें शाह ने राज्य में आक्रामक राजनीतिक रुख अपनाने का संकेत दिया है। शाह ने यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार में भ्रष्टाचार के कारण पश्चिम बंगाल का विकास रुक गया है। मोदी द्वारा शुरू की गई सभी लाभकारी योजनाएं यहां टोल सिंडिकेट की शिकार हो गई हैं। पिछले 14 वर्षों से डर और भ्रष्टाचार पश्चिम बंगाल की पहचान बन गए हैं। 15 अप्रैल, 2026 के बाद, जब पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार बनेगी, तब हम बंगाल की विरासत और संस्कृति को पुनर्जीवित करने का कार्य शुरू करेंगे। यह %बंगा भूमि% हमारे लिए बहुत महत्व रखती है ज्योंकि भाजपा का गठन डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था, जो यहां के एक बड़े नेता थे। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा और असम में घुसपैठ रुक गई है, जबकि पश्चिम बंगाल में यह जारी है। शाह ने दावा किया कि ममता बनर्जी राजनीतिक उद्देश्यों के लिए घुसपैठ जारी रखना चाहती हैं, जिसका मकसद उनके अनुसार अपना वोट बैंक बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि ममता, आज मैं आपसे एक सीधा सा सवाल पूछना चाहता हूं। कौन सी सरकार सीमा पर बाड़ लगाने के लिए जमीन देने से इनकार करती है? मैं खुद इसका जवाब दूंगा - यह आपकी सरकार है जो सीमा पर बाड़ लगाने के लिए जमीन नहीं देती। फिर मैं पूछना चाहता हूं कि घुसपैठिए सबसे पहले बंगाल में ज्यों प्रवेश करते हैं? आपके पटवारी और पुलिस स्टेशन ज़्या कर रहे हैं? इन घुसपैठियों को वापस ज्यों नहीं भेजा जा रहा है? ज़्या बंगाल सरकार यह बता सकती है कि असम और त्रिपुरा में घुसपैठ ज्यों रुक गई है? यह सिर्फ बंगाल में हो रही है ज्योंकि यह आपके शासनकाल में हो रहा है। आप अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए बंगाल की जनसंज़्या संरचना बदलना चाहती हैं। शाह ने जोर देकर कहा कि पश्चिम बंगाल की सीमा से घुसपैठ राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। उन्होंने राज्य में भाजपा सरकार बनाने का समर्थन किया ताकि घुसपैठ से निपटने के लिए बंगाल की सीमाओं को सील किया जा सके। शाह ने कहा कि बंगाल की सीमाओं से घुसपैठ सिर्फ राज्य का मुद्दा नहीं है; यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। अगर हम देश की संस्कृति की रक्षा करना चाहते हैं और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो हमें ऐसी सरकार बनानी होगी जो बंगाल की सीमाओं को सील कर दे। टीएमसी ऐसा नहीं कर सकती। सिर्फ भाजपा ही कर सकती है। विश्वास से भरे शज़्दों में उन्होंने कहा कि भाजपा पश्चिम बंगाल में दो-तिहाई बहुमत से सरकार बनाएगी।

विविध समाचार

पंजाब विधानसभा में वीबी-जी राम जी' कानून के खिलाफ प्रस्ताव लाना संविधान के विरुद्ध-शिवराज सिंह चौहान

नयी दिल्ली ३०/१२ (संवाददाता): केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को पंजाब विधानसभा में विकसित भारत- रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) यानी 'वीबी-जी राम जी' कानून के खिलाफ प्रस्ताव पेश किए जाने को संविधान और संघीय ढांचे की मूल भावना के विरुद्ध करार दिया और कहा कि संसद द्वारा पारित कानून को मानना राज्यों की संवैधानिक जिज़्मेदारी है। राजधानी भोपाल स्थित अपने आवास पर आयोजित एक संवाददाता सज़्मेलन को संबोधित करते हुए चौहान ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर भी निशाना साधा और कहा कि वह कल्पना लोक में रहते हैं और देश की हकीकत से उनका कोई लेना-देना नहीं है।

उन्होंने कहा, बिना मंत्री परिषद और कैबिनेट के काम चलने की बात कहना केवल भ्रम फैलाना है। मन में जो आया, वह कह देना जिज़्मेदार राजनीति नहीं है।

ज्ञात हो कि राहुल गांधी ने पिछले दिनों कहा था कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल से पूछे बिना और मामले का अध्ययन किए बिना अकेले ही महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को खत्म कर दिया। चौहान ने पंजाब विधानसभा में इस विधेयक के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव का उल्लेख करते हुए कहा कि ये अंध विरोध की राजनीति है और कुछ लोग केवल विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं, जिसका लोकतंत्र और संवैधानिक मर्यादाओं से कोई लेना-देना नहीं है।

उन्होंने कहा, अगर संसद में कोई कानून बनता है तो विधानसभा में उसके खिलाफ प्रस्ताव पारित करना हमारे संवैधानिक ढांचे की भावना के खिलाफ है।

केंद्रीय मंत्री ने सवाल उठाया कि ज़्या यह उचित होगा कि राज्य के कानून के खिलाफ जिला पंचायत, जनपद पंचायत या ग्राम पंचायत प्रस्ताव पारित करने लगे? उन्होंने स्पष्ट किया कि संसद द्वारा पारित कानूनों को मानना केंद्र और सभी राज्यों की संवैधानिक जिज़्मेदारी है। उन्होंने कहा, पंजाब सरकार और विधानसभा में कुछ दल जो कर रहे हैं, वह अलोकतांत्रिक, अमर्यादित और संविधान की मूल भावना के खिलाफ है।

चौहान ने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि पंजाब में मनरेगा सहित कई योजनाओं में व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार के मामलेसामने आए हैं लेकिन न तो दोषियों पर कार्रवाई की गई और न ही गबन की गई राशि की वसूली हुई। उन्होंने दावा किया कि पंजाब में 13 हजार 304 ग्राम पंचायतों में से केवल 5 हजार 915 में ही सोशल ऑडिट हुआ है। उन्होंने कहा, रिपोर्ट में करीब 10 हजार 653 विज़ीय गबन के मामले सामने आए, लेकिन इनमें किसी पर कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि मनरेगा में जिन गतिविधियों की अनुमति ही नहीं थीं उन पर भी अनियमित खर्च किया गया।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मजदूर शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें मजदूरी तक नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा, भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए काम नहीं किया जाता, पकड़े जाने पर भी कार्रवाई नहीं होती, और दूसरी तरफ विधानसभा में संसद के कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने की बात होती है। यह अलोकतांत्रिक सोच है, जिसकी मैं निंदा करता हूं। उल्लेखनीय है कि आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने मंगलवार को पंजाब विधानसभा में जी राम जी कानून के खिलाफ एक प्रस्ताव पेश किया और भाजपा नीत केंद्र सरकार पर मनरेगा को खत्म करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। राज्य के ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंड ने विधानसभा के एक दिवसीय सत्र के दौरान चर्चा के लिए सदन में प्रस्ताव पेश किया। सोंड ने कहा कि यह अधिनियम गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों, अनुसूचित जाति समुदायों और ग्रामीण मजदूरों को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा जो जीवित रहने के लिए मनरेगा पर निर्भर हैं।

शकुनि का चेला दुशासन! ममता का अमित शाह पर तीखा हमला, बंगाल में सियासी महाभारत

कोलकाता ३०/१२ (संवाददाता): पश्चिम बंगाल की मुज़्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को केंद्रीय मंत्री अमित शाह पर करारा जवाब दिया, जिन्होंने टीएमसी सरकार की तुलना भय और भ्रष्टाचार से की थी और उन पर सीमा बाड़ लगाने के लिए जमीन देने से इनकार करने का आरोप लगाया था। ममता बनर्जी ने जवाब में भाजपा नेताओं की तुलना महाभारत महाकाव्य के पौराणिक पात्रों दुर्योधन और दुशासन से की। शाह के आरोपों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि टीएमसी सरकार ने पेट्रापोल और अंडाल में बाड़ लगाने के लिए जमीन दी थी। एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 14 साल पहले की स्थिति याद कीजिए, लोग डरे हुए थे। बांकुरा के लिए बहुत विकास कार्य किए गए और जल संकट को दूर करने के लिए बहुत कुछ किया गया। चुनाव आ गए हैं और एसआईआर के नाम पर लोगों को परेशान किया जा रहा है। टीएमसी नेता ने आगे कहा कि बंगाल में दुशासन आ गया है। चुनाव आते ही दुशासन और दुर्योधन प्रकट होने लगते हैं। यह शकुनी का शिष्य दुशासन है, जो सूचना जुटाने आया है। आज वे कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने जमीन नहीं दी। अगर मैंने जमीन नहीं दी होती तो ज़्या होता? पेट्रापोल में जमीन किसने दी? आंदल में जमीन किसने दी? जबकि केंद्रीय मंत्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल की सीमा से घुसपैठ राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, ममता बनर्जी ने पलटवार करते हुए कहा कि वे कहते हैं कि प्रवासी केवल बंगाल से आते हैं। अगर ऐसा है, तो ज़्या आपने पहलगाम में हमला करवाया था? दिल्ली में हुई घटना के पीछे कौन था? भ्रष्ट भाजपा पार्टी। वे सर के नाम पर लोगों को परेशान कर रहे हैं। केवल आप और आपका बेटा खाएंगे, और हम उपदेश सुनते रहेंगे। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची का विशेष गहन संशोधन और प्रवासियों का आगमन गरमागरम मुद्दे बन गए हैं, जिन्हें राज्य में आगामी 2026 विधानसभा चुनावों में मुद्दा बनाया जा सकता है।

शाह ने कहा कि त्रिपुरा और असम में घुसपैठ रुक गई है, जबकि पश्चिम बंगाल में यह जारी है। शाह ने दावा किया कि ममता बनर्जी राजनीतिक उद्देश्यों के लिए घुसपैठ जारी रखना चाहती हैं, जिसका मकसद अपना वोट बैंक बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि ममता, आज मैं आपसे एक सीधा सा सवाल पूछना चाहता हूं। कौन सी सरकार सीमा पर बाड़ लगाने के लिए जमीन देने से इनकार करती है? मैं खुद इसका जवाब दूंगा - यह आपकी सरकार है जो सीमा पर बाड़ लगाने के लिए जमीन नहीं देती। फिर मैं पूछना चाहता हूं कि घुसपैठिए सबसे पहले बंगाल में ज़्यों घुसते हैं?

आपके पटवारी और पुलिस स्टेशन ज़्या कर रहे हैं? इन घुसपैठियों को वापस ज़्यों नहीं भेजा जा रहा है? ज़्या बंगाल सरकार यह बता सकती है कि असम और त्रिपुरा में घुसपैठ ज़्यों रुक गई है? यह सिर्फ बंगाल में हो रहा है ज़्योंकि यह सब आपकी सरकार के शासनकाल में हो रहा है। आप अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए बंगाल की जनसंज़्या संरचना बदलना चाहती हैं।

संभल की जामा मस्जिद की नहीं होगी रंगाई-पुताई, सिर्फ साफ सफाई की इजाजत

संभल ३०/१२ (संवाददाता): इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ;एएसआईद्ध को संभल में जामा मस्जिद के परिसर को साफ करने का निर्देश दियाए लेकिन मस्जिद की सफेदी करने का आदेश पारित नहीं किया। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने यह आदेश जामा मस्जिद प्रबंधन समिति के एक आवेदन पर पारित कियाए जिसमें रमजान से पहले मस्जिद की सफेदी और सफाई की अनुमति मांगी गई थी। गुरुवार को अदालत ने एएसआई को मस्जिद स्थल का तुरंत निरीक्षण करने और तीन अधिकारियों की एक टीम नियुक्त करने का निर्देश दियाए जो शुक्रवार सुबह 10 बजे तक इस संबंध में एक रिपोर्ट पेश की।एएसआई की रिपोर्ट के मुताबिकए मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में सिरेमिक पेंट है और फिलहाल इसे सफेद करने की कोई जरूरत नहीं है। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान मस्जिद समिति की ओर से पेश वरिष्ठ वकील एस एफ ए नकवी ने कहा कि वे चाहते हैं कि केवल सफेदी और रोशनी का काम किया जाए। इस पर कोर्ट ने एएसआई को परिसर में धूल साफकरने और घास साफकरने को कहा। नकवी ने अदालत को आश्वासन दिया कि सफाई के दौरान कोई बाधा उत्पन्न नहीं की जाएगी जबकि राज्य के महाधिवक्ता ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखी जाएगी।

संभल पुलिस ने इस दावे का विरोध करते हुए तर्क दिया कि समिति को किसी भी रखरखाव कार्य के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से अनुमति की आवश्यकता है। जवाब मेंए मस्जिद अधिकारियों ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और कहा कि अतीत में अन्य विशेष अवसरों के लिए भी इसी तरह का काम किया गया था। मस्जिद अधिकारियों ने यह भी दावा किया कि पुलिस की आपज़ि ने धार्मिक गतिविधियों का स्वतंत्र रूप से अज़्यास करने और प्रबंधन करने के उनके अधिकार का उल्लंघन किया हैए जिसकी गारंटी संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 द्वारा दी गई है।

बेंगलुरू में भगदड़, पुलिस ने आरसीबी और कंपनी के अधिकारियों को हिरासत में लिया

बेंगलुरु ३०/१२ (संवाददाता): चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ के सिलसिले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) और आयोजन का प्रबंधन करने वाली कंपनी 'डीएनए एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड' के अधिकारियों को हिरासत में लिया गया। पुलिस सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के फाइनल में आरसीबी की जीत के जश्न में भाग लेने के लिए बुधवार को यहां चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास बड़ी संज़्या में क्रिकेट प्रेमियों के जुटने के बाद मची भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई और 56 से अधिक लोग घायल हो गए।

इन अधिकारियों को अपराध शाखा और बेंगलुरु पुलिस के संयुक्त अभियान के तहत हिरासत में लिया गया। सूत्रों ने बताया कि आरसीबी के विपणन एवं राजस्व प्रमुख निखिल सोसले, डीएनए एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के सुनील मैथ्यू और किरण कुमार से पूछताछ की जा रही है। उन्होंने कहा कि बाद में आगे की प्रक्रिया की जाएगी। इनमें से कुछ को कथित तौर पर केज़्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (केआईए) से हिरासत में लिया गया जो शहर के बाहरी इलाके में स्थित है। पुलिस ने आरसीबी, डीएनए और कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (केएससीए) के खिलाफ बृहस्पतिवार को प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद यह कार्रवाई की। कर्नाटक के मुज़्यमंत्री सिद्धरमैया ने राज्य के पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक को बृहस्पतिवार को निर्देश दिया था कि भगदड़ के सिलसिले में आरसीबी और डीएनए इवेंट मैनेजर एवं केएससी के प्रतिनिधियों को तुरंत गिरज़्तार किया जाए ज़्योंकि प्रथम दृष्टया उन्होंने ''लापरवाही'' की।

बीजापुर में सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में नज़्सली नेता ढेर

बीजापुर ३०/१२ (संवाददाता): छज़ीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में नज़्सलियों का एक शीर्ष नेता मारा गया है। पुलिस अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। सूत्रों के अनुसार माओवादियों की केंद्रीय समिति कासदस्य गौतम उर्फ सुधाकर इस मुठभेड़ में मारा गया है।हालांकि, इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बीजापुर जिले के इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में केंद्रीय समिति के सदस्य गौतम उर्फ सुधाकर, तेलंगाना राज्य समिति के सदस्य बांदी प्रकाश, दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के सदस्य पप्पा राव तथा कुछ अन्य सशस्त्र माओवादी कैडरों की मौजूदगी की सूचना पर जिला रिजर्व गार्ड (डीआरजी), विशेष कार्य बल (एसटीएफ) और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की कोबरा बटालियन के संयुक्त दल को नज़्सल विरोधी अभियान में रवाना किया गया था।

उन्होंने बताया कि क्षेत्र में नज़्सल विरोधी अभियान के दौरान सुरक्षाबलों और नज़्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ में नज़्सलियों के एक शीर्ष नेता को मार गिराया है।

अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्र में तलाशी अभियान जारी है। घटनास्थल से बरामद शव और वस्तुओं के संबंध में अधिक जानकारी एकत्र की जा रही है। उन्होंने बताया कि इस मुठभेड़ में बड़ी सफलता मिलने की भी जानकारी है। इससे पहले, सुरक्षाबलों ने 21 मई को राज्य के बीजापुर-नारायणपुर जिले की सीमा पर स्थित अबूझमाड़ के जंगल में मुठभेड़ के दौरान प्रतिबंधित भारतीय कज़्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के महासचिव बसवराजू और 26 अन्य नज़्सलियों को मार गिराया था।

महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फड्णवीस के दफ्तर पर हमले की पाकिस्तान की साजिश? मुंबई पुलिस को मिली धमकी

मुंबई ३०/१२ (संवाददाता):मुंबई ट्रैफिक पुलिस को व्हाट्सएप पर एक संदेश मिला हैए जिसमें भेजने वाले ने मुज़्यमंत्री देवेंद्र फड्णवीस के कार्यालय पर हमले की योजना की बात कही है। वर्ली पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह संदेश एक पाकिस्तानी फोन नंबर से वर्ली ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल रूम को भेजा गया थाए जिससे सुरक्षा संबंधी गंभीर चिंताएं पैदा हो गई हैं।

यातायात पुलिस को बुधवार दोपहर को एक पाकिस्तानी नंबर से व्हाट्सएप पर यह धमकी भरा संदेश मिला। संदेश भेजने वाले ने खुद को मलिक शाहबाज हुमायूं राजा देव बताया है। यह पता लगाने के लिए जांच चल रही है कि भेजने वाला भारतीय है या विदेशी। यह ताजा धमकी एक अन्य ईमेल के बाद आई हैए जिसने मुंबई पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा है। पिछले हज़्ते महाराष्ट्र के उपमुज़्यमंत्री एकनाथ शिंदे को निशाना बनाकर बम की धमकी दी गई थी।

शिंदे के वाहन को उड़ाने की धमकी देने वाला ईमेल गोरेगांव और जेजे मार्ग पुलिस स्टेशनए मुज़्यमंत्री कार्यालय ;सीएमओद्ध और मंत्रालय सहित कई आधिकारिक खातों को भेजा गया था। अधिकारियों ने धमकी का जवाब देने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। गोरेगांव पुलिस ने पूछताछ के लिए एक संदिग्ध को हिरासत में लियाए जबकि मुंबई क्राइम ब्रांच द्वारा समानांतर जांच में आरोपी की पहचान और गिरज़्तारी हुई।

पूछताछ के दौरानए संदिग्ध ने कथित तौर पर ईमेल भेजने की बात कबूल कीए लेकिन जांचकर्ता अब संदेश की सटीक उत्पज़ि और इस कृत्य के पीछे किसी भी संभावित मकसद का पता लगाने के लिए काम कर रहे हैं। मानक प्रक्रिया का पालन करते हुएए भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं के तहत तुरंत एक प्राथमिकी दर्ज की गईए जिसमें आपराधिक धमकी के लिए धारा 351 ;3द्ध और 351 ;4द्ध और सार्वजनिक शरारत के लिए बयानों के लिए धारा 353 ;2द्ध शामिल हैं। धमकी की डिजिटल प्रकृति को संबोधित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत अतिरिक्त प्रावधान भी लागू किए गए।

उपमुज़्यमंत्री एकनाथ शिंदे को पिछले महीने भी इसी तरह की बम की धमकी मिली थीए जिसके बाद 27 वर्षीय संदिग्ध को गिरज़्तार किया गया था। उस समय शिंदेए मुज़्यमंत्री देवेंद्र फड्णवीस और जितेंद्र पवार के साथ दिल्ली के नए मुज़्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए दिल्ली में थे।

नीतीश के मंत्री ने प्रशांत किशोर पर ठोका मानहानि का केस, बोले- अभी तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ है जो...

पटना ३०/१२ (संवाददाता): बिहार के मंत्री और जेडीयू के वरिष्ठ नेता अशोक चौधरी ने मंगलवार को जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। किशोर ने आरोप लगाया था कि चौधरी ने अपनी बेटी के लिए लोकसभा का टिकट हासिल करने के लिए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को रिश्वत दी थी।

चौधरी, जिनकी बेटी शांभवी समस्तीपुर के आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) की सांसद हैं। जेडी(यू) के राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि प्रशांत किशोर द्वारा मेरी बेटी और मेरे खिलाफ आपज़िजनक टिप्पणी करने के बाद, मैंने उन्हें कानूनी नोटिस भेजा, जिसका उनका जवाब असंतोषजनक था। उन्होंने जो कहा उसके लिए उन्हें स्पष्ट रूप से कोई पछतावा नहीं है। उन्होंने कहा कि इसलिए मैंने कानूनी उपाय का सहारा लिया है। मैं प्रशांत किशोर को चुनौती देता हूं कि वे साबित करें कि मैंने चिराग पासवान को पैसे दिए थे या फिर माफी मांगकर अपने आरोप वापस लें। अगर जरूरत पड़ी तो मैं इस लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने के लिए दृढ़ संकल्पित हूं।चौधरी ने पूर्व चुनाव रणनीतिकार किशोर जो कुछ समय तक जेडी(यू) से भी जुड़े रहे थे को एक राजनीतिक व्यापारी बताया, जिन्होंने शुल्क लेकर सभी तरह की पार्टियों को अपनी सेवाएं देने की पेशकश की है।

कलिंग समाचार
THE KALINGA SAMACHAR
(A Hindi Daily News Paper)
PUBLISHED FROM ODISHA, JHARKHAND & CHATTISHGARH
FOR NEWS AND ADVERTISEMENT CONTACT
AT: QRS. NO. B/204, SECTOR-16
ROURKELA, PH. 0661-2646999
PRAKASH KUMAR DHAL (EDITOR)
E-mail: thekalingasamachar@gmail.com

विविध समाचार

भेड़ पालन

विश्व की भेड़ जनसंख्या की लगभग 4 प्रतिशत भेड़ भारत में हैं। भारत सरकार की साल 2003 की मवेशी गणना के अनुसार, देश में लगभग 6.147 करोड़ भेड़ हैं। देशभर में लगभग 50 लाख परिवार भेड़ पालन और इससे जुड़े हुए रोजगार में लगे हुए हैं। भेड़ सामान्यत: कम वर्षा वाले शुष्क क्षेत्रों में पायी जाती हैं। भारत में प्रति भेड़ से प्रति वर्ष 1 किलोग्राम से भी कम ऊन का उत्पादन होता है।

मांस उत्पादन की दृष्टि से भारतीय भेड़ों का औसत वजन 25 किलो से 30 किलो के बीच होता है। ऐसे में भेड़ों की नस्लों में सुधार करके उनसे कैसे अधिक ऊन, दूध और मांस प्राप्त किया जा सके, इसके लिए केन्द्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान काम करता है।

भेड़ ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक संरचना से जुड़ा है। इससे हमें मांस, दूध, ऊन, जैविक खाद तथा अन्य उपयोगी सामग्री मिलती है। इनके पालन-पोषण से भेड़ पालकों को अनेक फायदे हैं। अत: निम्नलिखित बातों पर उचित ध्यान देना चाहिए

प्रजनन एवं नस्ल

अच्छी नस्लों की देसी, विदेशी एवं संकर प्रजातियों का चुनाव अपने उद्देश्य के अनुसार करनी चाहिए। मांस के लिए मालपुरा, जैसलमेरी, मांडिया, मारवाड़ी, नाली शाहाबादी एवं छोटानागपुरी तथा ऊन के लिए बीकानेरी, मेरीनो, कोरीडेल, रमबुये इत्यादि का चुनाव करना चाहिए।

दरी ऊन के लिए मालपुरा, जैसलमेरी, मारवाड़ी, शाहाबादी एवं छोटानागपुरी इत्यादि मुख्य है। इनका प्रजनन मौसम के अनुसार करना चाहिए। 12-18 महीने की उम्र मादा के प्रजनन के लिए उचित मानी गई है।

अधिक गर्मी तथा बरसात के मौसम में प्रजनन तथा भेड़ के बच्चों का जन्म नहीं होना चाहिए। इससे मृत्यु दर बढ़ती है।

रतिकाल एवं रति चक्र

भेड़ में प्राय: 12-48 घंटे का रतिकाल होता है। इस काल में ही औसतन 20-30 घंटे के अन्दर पाल दिलवाना चाहिए। रति चक्र प्राय: 12-24 दिनों का होता है।

ऊन

महीन ऊन बच्चों के लिए उपयोगी है तथा मोटे ऊन दरी तथा कालीन के लिए अच्छे माने गये हैं। गर्मी तथा बरसात के पहले ही इनके शरीर से ऊन की कटाई कर लेनी चाहिए। शरीर पर ऊन रहने से गर्मी तथा बरसात का बुरा प्रभाव पड़ता है। जाड़ा जाने के पहले ही ऊन की कटाई कर लेनी चाहिए। जाड़े में स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। शरीर के वजन का लगभग 40-50 प्रतिशत मांस के रूप में प्राप्त होता है।

पोषण एवं चराई

सुबह 7 से 10 बजे तथा शाम 3-6 बजे के बीच में भेड़ों को चराना तथा दोपहर में आराम देना चाहिए। गाभिन भेड़ को 250-300 ग्राम दाना प्रति भेड़ सुबह या शाम में देना चाहिए।

मेमने की देखभाल

भेड़ के बच्चे को पैदा होने के बाद तुरंत फेनसा पिलाना चाहिए। इससे पोषण तथा रोग निरोधक शक्ति प्राप्त होती है। दूध सुबह-शाम पिलाना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए के बच्चा भूखा न रह जाये।

रोगों की रोकथाम

समय-समय पर भेड़ों के मल कृमि की जाँच करनी चाहिए और पशु चिकित्सक की सलाह के अनुसार कृमि-नाशक दवा पिलानी चाहिए। चर्म रोगों में चर्मरोग निरोधक दवाई देनी चाहिए।

रखने का स्थान

भेड़ के रहने का स्थान स्वच्छ तथा खुला होना चाहिए। गर्मी, बरसात तथा जाड़ा के मौसम में बचाव होना जरूरी है। पीने के लिए स्वच्छ पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहना चाहिए।

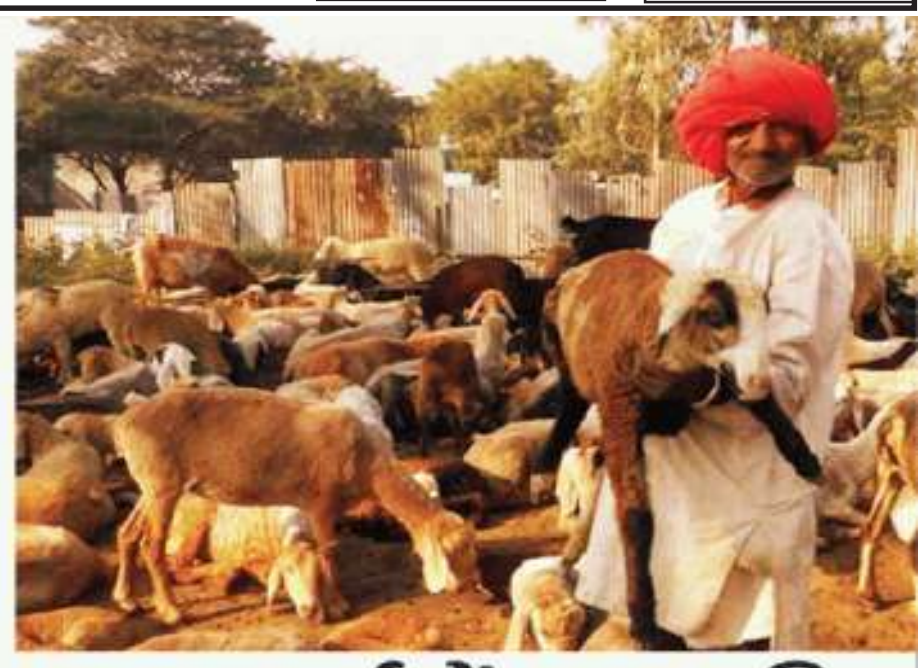

कम खर्च में लखपति बना देगा भेड़ पालन

किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से पशु पालन बिजनेस पर काफी फोकस किया जाता है। किसान भेड़ पालन कर उनके ऊन, खाद, दूध और चमड़े से मोटी कमाई सकते है

देश में किसानों के लिए खेती के अलावा पशु पालन का भी बेहतर विकल्प है। पशु पालन से किसान मोटी कमाई कर सकते हैं। भारत के ज्यादातर इलाकों में पशुओं की अलग-अलग प्रजातियों के साथ पशुपालन बिजनेस चल रहे हैं। इनमें गाय, भैंस, बकरी, और ऊंट जैसे पशुओं को डेयरी फार्मिंग के मकसद से पाला जाता है। ऐसे ही किसान भेड़ पालनके जरिए मोटी कमाई कर सकते है। भेड़ों से ऊन, खाद, दूध, चमड़ा जैसे कई सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। इस बिजनेस को बेहद कम निवेश के साथ शुरू कर सकते हैं। किसानों के बीच यह बिजनेस तेजी से पॉपुलर हो रहा है। भेड़ पालन शुरू करने के लिए जरूरी है कि भेड़ की बेहतर प्रजातियों को ही चुनें। जिससे अच्छी मात्रा में दूध और ऊन मिल सके। भारत में आमदनी बढ़ाने वाली भेड़ की प्रजातियों में मालपुरा, जैसलमेरी, मंडिया, मारवाड़ी, बीकानेरी, मैरिनो, कोरिडायलरा मबुतु, छोटा नागपुरी और शहाबाबाद जैसी प्रजातियां काफी लोकप्रिय है।

सरकार से मिलती है सब्सिडी

किसानों की कमाई दोगुना करने के मकदस से सरकार भी कई तरह की योजनाएं चला रही है। केंद्र सरकार के नेशनल लाइवस्टॉक मिशन के तहत भेड़ पालन पालन के लिए 50 फीसदी तक की सब्सिडी मुहैया कराई जाती है। इसके अलावा कई राज्य सरकार अपने-अपने स्तर पर किसानों को भेड़ पालन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए आर्थिक मदद करते है। भेड़ शाकाहारी पशु होते हैं। इन्हें हरा चारा और पत्तियां काफी पसंद है। भेड़ का गोबर भी बहुत अच्छा उर्वरक माना जाता है। इनके उपयोग से खेत की उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। आमतौर पर भेड़ों का जीवन 7-8 साल ही होता है। भेड़ पालन से बंपर कमाई के लिए उनकी साफ-सफाई और तबीयत पर भरपूर ध्यान देने की जरूरत है।

लागत और कमाई

अगर आप 15-20 भेड़ों के साथ पशुपालन शुरू करना चाहते हैं, तो प्रजातियों के हिसाब से एक भेड़ 3000-8000 रुपये की कीमत पर मिलती है। यहीं 20 भेड़ों की खरीद पर करीब 1 लाख से 1.5 लाख रुपये तक का खर्च आता है। विशेषज्ञों की मानें तो 20 भेड़ों के लिये 500 वर्गफुट का तबेला काफी रहता है। जिसे 30,000-40,000 रुपये की लागत पर तैयार किया जा सकता है। भेड़ के शरीर पर बहुत नरम और लंबे रोयें होते है। जिनसे ऊन मिलता है. इसके ऊन से ही कई तरह के गर्म कपड़े बनाए जाते है। भेड़ अपने जीवनकाल में भरपूर ऊन पैदा करके पशुपालकों को लखपति बना देती है।

सुरक्षित फसल रामतिल

भारत में इस फसल की खेती 5.42 लाख हेक्टेयर में प्रतिवर्ष की जाती है। इसकी औसत उत्पादन क्षमता 299 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से कुल उत्पादन 1.62 लाख टन प्रतिवर्ष होता है। अविभाजित मध्यप्रदेश राज्य रामतिल के क्षेत्राच्छादन एवं उत्पादन की दृष्टि से अग्रणी राज्य था। डिण्डोरी जिले में लगभग 35 हजार हेक्टेयर में इसकी खेती की जाती है जिसका औसत उत्पादन 200 कि.ग्राम प्रति हेक्टेयर है। यदि फसल को अच्छे प्रबंधन के साथ लगाया जाए तो उपज 5 से 6 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक प्राप्त की जाती सकती है। अनुकूल उत्पादन अवस्थाओं में इसका उत्पादन 6 से 8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक भी प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार के अच्छे उत्पादन प्राप्त करने के लिये यह आवश्यक है कि कृषक उन्नतशील किस्मों का प्रयोग करें। मौसम के अनुसार उपयुक्त समय पर बुआई करें।

भूमि का चुनाव

यह फसल गहरी काली मिट्टी से भुरभुरी, रेतीली भूमियों जिसमें जल निकास की उत्तम क्षमता हो, में सफलतापूर्वक लगाई जा सकती है। अच्छी गहराई वाली मिट्टी जिसका पी.एच. मान 5.5 से 6.5 के बीच हो इस फसल के लिए अति उत्तम मिट्टी होती है। हल्की क्षारीय एवं लवणीय भूमि में भी इसकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। परंतु भारी काली कपास वाली भूमि एवं पानी रुकने वाली भूमियां इसके खेती हेतु उपयुक्त नहीं है।

फसल पद्धति

रामतिल फसल की बुआई सामान्यत: मध्य अगस्त में की जाती है। अत: इसके पूर्व एक फसल उड़द, बरबटी या फ्रेंचबीन की ले सकते हैं। डिंडोरी जिले में इस फसल को कुटकी की फसल लेने के बाद भी लेने की संभावना है। परंतु इसके लिये यह आवश्यक होगा कि पहली फसल की बुआई मई के अंत में या जून के प्रथम सप्ताह तक पूरी हो जानी चाहिए, क्योंकि देर से बुआई करने पर रामतिल की बुआई में देरी होगी जिसका उत्पादकता पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

उन्नत किस्में

अच्छी उपज लेने के लिए उपयुक्त किस्म का चयन किया जाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। भूमि एवं बोने के समय के अनुसार उपयुक्त किस्म का चुनाव करना चाहिए। अखिल भारतीय समन्वित तिल एवं रामतिल अनुसंधान परियोजना के द्वारा अनेक उन्नत किस्मों की अनुशंसा की गई है। डिंडोरी क्षेत्र के लिये अनुशंसित किस्म के प्रमुख गुण एवं लक्षण तालिका में प्रस्तुत हैं।

बीज दर

शुद्ध फसल हेतु 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है।

बीजोपचार

फसल को बीज एवं मिट्टी जनित रोग के संभावित आक्रमण को टालने के लिए बीजोपचार आवश्यक है। थायरम या केप्टान नामक दवाई की 3 ग्राम मात्रा से एक किलोग्राम बीज को उपचारित करना चाहिए। बुआई के 12 घंटे पूर्व फास्फोरस घोलक जीवाणु (पी.एस.बी.) कल्चर 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर उपचारित कर छायादार स्थान में सुखाना चाहिए, इससे उत्पादन में वृद्धि होती है।

बुआई विधि

सामान्यत: रामतिल की बुआई छिड़काव पद्धति से की जाती है इससे प्रति क्षेत्र में वांछित पौध संख्या नहीं मिल पाती है। इसकी अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए कतार से बुआई करना चाहिए एवं एक कतार से दूसरे कतार के बीच में 30 से.मी. (1 फीट) का अंतर होना चाहिए। बुआई के पूर्व एक भाग बीज को 20 भाग रेत या भुरभुरी गोबर खाद या राख के साथ मिलाकर बुआई करना चाहिए। इससे प्रति इकाई क्षेत्र में वांछित पौधा संख्या प्राप्त होगी एवं पौध छंटाई का कार्य नहीं करना पड़ता।

उर्वरक एवं खाद

रसायनिक उर्वरकों में नत्रजन 10 किलोग्राम, स्फुर 20 किलोग्राम एवं पोटाश 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बुआई के समय डालना चाहिए। बुआई के 30 से 35 दिन बाद 10 किलोग्राम नत्रजन प्रति हेक्टेयर की मात्रा भूमि में नमी उपलब्ध पर डालने से उत्पादन में वृद्धि होती है।

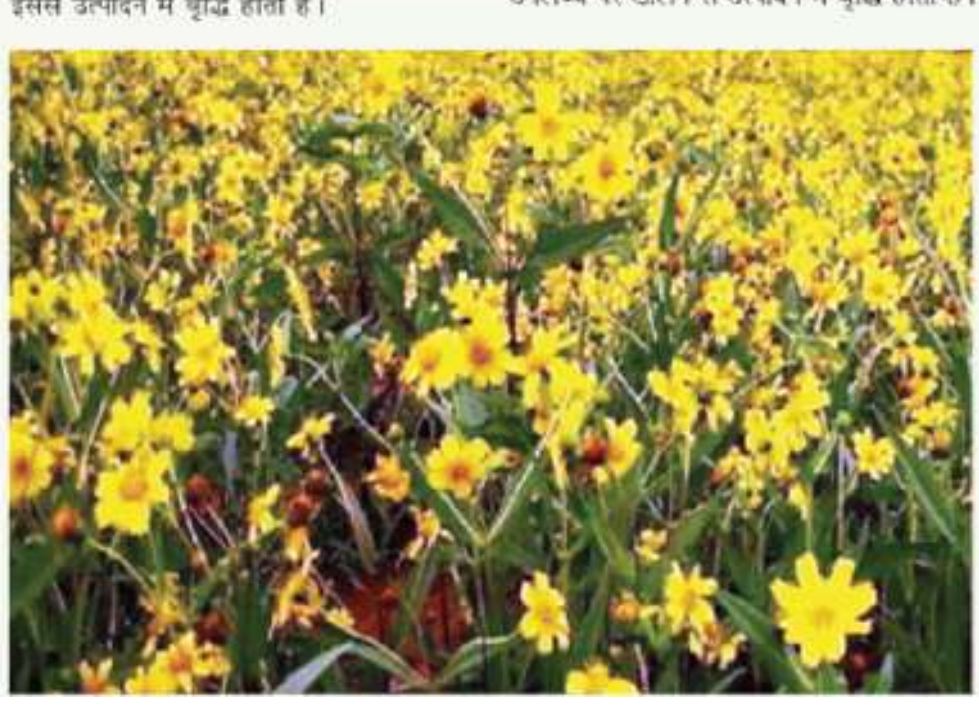

नींदा नियंत्रण

रामतिल फसल में पहली निंदाई - गुड़ाई बुआई के 15-20 दिन बाद करना चाहिए। यदि आवश्यक है तो दूसरी निंदाई -गुड़ाई बुआई के लगभग 35 - 40 दिन बाद करें। यह कार्य खड़ी फसल में नत्रजन के छिड़काव से पहले कर लेना चाहिए। रामतिल की फसल से डिण्डोरी क्षेत्र में अमरबेल की समस्या विकराल रूप लेती जा रही है। जिसके कारण कृषक बंधु इसकी खेती को छोड़ रहे है परंतु अनुसंधान के आधार पर रसायनिक दवा के उपचार से अमरबेल का समूल नाश किया जा सकता है। इसके लिए नींदानाशक दवा पेन्डीमिथालीन 0.75 से 1.5 किलो सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर की दर से 500 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए अथवा लासो दानेदार 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए।

कटाई एवं गहाई

रामतिल की फसल किस्मानुसार 90 से 120 दिनों के बीच पककर तैयार हो जाती है। जब पौधे की पत्तियां सूखकर गिरने लगे एवं फली का शीर्ष भाग भूरे एवं काले रंग का दिखने लगे तब फसल की कटाई करें। कटाई में देर करने पर बीज झड़ने का डर रहता है। कटाई के उपरांत पौधों को बंडल में बांधकर खेत में खुली धूप में एक सप्ताह तक सुखाकर गहाई करनी चाहिए।

आय - व्यय

परम्परागत तरीके से फसल लगाने से उपज 50 से 200 किलो ग्राम प्रति हेक्टेयर तक प्राप्त होती है। जिससे कुल आमदनी 2250 से 9000 रु. होती है। उन्नत काश्त तकनीक अपनाकर खेती करने से औसत उपज 500 से 600 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक प्राप्त होगी जिससे कुल आय 20,000 से 25000 रु. तक प्राप्त होगी।

कलिंग समाचार

संपादकीय

बुधवार 31 दिसंबर 2025

मनरेगा से जी राम जी

नाम बदलना भाजपा का पुराना शगल रहा है। सड़कों, स्टेशनों, चौराहों के साथ-साथ पुरानी सरकारों की शुरु की गई बहुत सी योजनाओं के नाम भाजपा सरकारें बदलती रही हैं, लेकिन इस बार मोदी सरकार ने एक ऐसी योजना पर राजनीति की है, जो ग्रामीण भारत की आजीविका के लिए बेहद जरूरी है। सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा का न केवल नाम बदला है, बल्कि इसमें काम के दिनों से लेकर केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय व्यवस्था को भी बदल दिया है। जिसके बाद एक बार फिर से मोदी सरकार की नीयत पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर मनरेगा को बदलने के पीछे क्या मंशा ग्राम पंचायतों से अधिकार छीनने और उन्हें कमजोर करने की है। ज्ञात हो कि मोदी सरकार ने लोकसभा में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण 2025 पेश किया। इसका संक्षिप्तीकरण वी बी- जी राम जी के तौर पर प्रचारित किया जा रहा है। राम शब्द का सियासी इस्तेमाल कितने तरीकों से किया जा सकता है, इसकी नयी-नयी मिसालें मोदी सरकार पेश कर रही है। राम मंदिर बनाने के लिए रथ यात्रा निकालने से लेकर बाबरी मस्जिद गिराकर उस जगह पर राम मंदिर के लिए पहले शिलान्यास करना, फिर राम मंदिर बनने के बाद उद्घाटन करना और इसके बाद मंदिर में धर्म ध्वजा फहराने जैसे काम किए गए, इसके बाद भी भाजपा को लगता है कि राम नाम को भुनाने की संभावनाएं अभी मौजूद हैं, लिहाजा अब महात्मा गांधी के नाम पर पिछले 20 सालों से चल रही ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को ही बदल दिया गया है। पिछले सप्ताह तक चर्चा थी कि भाजपा मनरेगा में महात्मा गांधी की जगह पूज्य बापू करना चाहती है। इस पर भी विपक्ष ने सवाल किया था कि आखिर महात्मा गांधी नाम से भाजपा को क्या तकलीफ है। लेकिन अब तो न केवल महात्मा गांधी शब्द हटाया गया है, बल्कि योजना ही बदलने की तैयारी है। जिसके बाद संसद का शीतकालीन सत्र में बड़ा विवाद बन गया है। विपक्ष ने मंगलवार को संसद परिसर में इस पर प्रदर्शन भी किया। प्रणिति शिंदे और कुमारी शैलजा समेत कुछ सांसद तो पुराने संसद भवन की छत पर चढ़कर गांधीजी के पोस्टर के साथ नारेबाजी करते दिखे। दरअसल मनरेगा को बदलने का यह प्रस्ताव ग्रामीण भारत की आजीविका से जुड़ा होने के कारण राजनीतिक और आर्थिक दोनों तरीके से संवेदनशील है। पांच साल पहले जब कोरोना की महामारी ने देश को आर्थिक तौर पर भी झकझोर कर रख दिया था, तब इसी मनरेगा के कारण ग्रामीण भारत में दो वक्त की रोटी का सहारा बना रहा। केंद्र की मोदी सरकार ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है और माना है कि मनरेगा से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सहारा मिला है। जबकि अपने पहले कार्यकाल में इसी मनरेगा का मजाक उड़ाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने इसे यूपीए सरकार का गड्ढा बताया था। जबकि मनरेगा इतना क्रांतिकारी कानून था कि 2005 में जब इसे लाया गया था, तब संसद में सभी राजनीतिक दलों ने इसका समर्थन किया था। मनरेगा ग्रामीण क्षेत्रों में हर परिवार को साल में 100 दिन के मजदूरी वाले काम की गारंटी देता है। जबकि नए विधेयक में मजदूरी के 125 दिन निर्धारित किए गए हैं, लेकिन इसमें न मानदेय बढ़ाया गया है, न ये तय है कि ग्रामीण किस तरह रोजगार की गारंटी पाएंगे, क्योंकि अब यह हक ग्राम पंचायतों का नहीं केंद्र का हो जाएगा। प्रियंका गांधी ने इस बारे में लोकसभा में कहा है कि मनरेगा मांग-आधारित है, जिसमें केंद्र सरकार की फंडिंग भी मांग के अनुसार होती है। लेकिन नए विधेयक में केंद्र नॉर्मेटिव फंडिंग के आधार पर वित्तपोषण करेगा। नॉर्मेटिव फंडिंग मतलब एक ऐसी प्रणाली जहां धन का आबंटन पूर्व-निर्धारित मानकों, मानदंडों या नियमों के आधार पर होगा, ग्राम सभा की जरूरत के मुताबिक नहीं। यानी किसी ग्राम सभा को अगर किसी कार्य के लिए ज्यादा धन की जरूरत होगी, तब भी केंद्र उसे वह मुहैया नहीं कराएगा, बल्कि जो पहले से तय है, उतना ही फंड जारी करेगा।

भाजपा बनी हिंदू महासभा

राजेन्द्र शर्मा

प. बंगाल, जो एक और ऐसा राज्य है जहां संघ-भाजपा अपनी सारी कोशिशों के बावजूद, अब तक सत्ता तक पहुंचने में कामयाब नहीं हुए हैं। सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के निलंबित विधायक, हुमायूं कबीर की अपने इलाके में बाबरी मस्जिद बनाने की घोषणा को, संघ-भाजपा ने बिना जरा भी समय गंवाए जवाबी सांप्रदायिक गोलबंदी का बहाना बना लिया। भाजपा के पर्ची से निकले अध्यक्ष (अभी कार्यकारी) नितिन नबीन ने जब राजधानी दिल्ली में भाजपा मु यालय में कुर्सी संभालने के बाद, अपने पहले बयान में सब का साथ, सब का विकास की बात की, तो सचमुच काफी अटपटा सा लगा। बेशक, ऐसा तो नहीं है कि भाजपा ने 2019 के चुनाव की जीत के बाद नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए इस नारे को आधिकारिक रूप से छोड़ ही दिया हो। वैसे आधिकारिक रूप से भाजपा ने छोड़ा तो संभवत:गांधीवादी समाजवाद को भी नहीं है, जिसे जनता पार्टी में विभाजन के बाद, उसके जनसंघ घटक के गिर्द 1980 में भाजपा के गठन के समय, अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में इस पार्टी की मूल विचारधारा के रूप में स्वीकार किया गया था। बहरहाल, गांधीवादी समाजवाद के साथ कभी जोर-शोर से घोषित अपने नाते को भाजपा अब तक करीब-करीब भुला ही चुकी है और इस भूले हुए रिश्ते को याद करने में भी, अब उसे किसी पुरानी भूल को याद करने जैसी शर्म ही आती लगती है।उस हद तक तो नहीं, फिर भी कुछ-कुछ उसी तरह पिछले कुछ वर्षों में और खासतौर पर 2024 के आरंभ में अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का पूरा श्रेय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में संघ-भाजपा द्वारा आधिकारिक रूप से लूटे जाने के बाद से, उनकी बयानबाजी में से यह नारा करीब-करीब गायब ही हो चुका है। हां! भूले-भटके किसी बहस में संघ-भाजपा के अल्पसं यक-विरोधी और खासतौर पर मुस्लिमविरोधी होने की आलोचनाओं के जवाब में जरूर, ढाल की तरह इस नारे की दुहाई का इस्तेमाल जरूर देखने को मिल सकता है। कहने की जरूरत नहीं है कि 2019 में नरेंद्र मोदी की दूसरी पारी की शुरूआत में जब यह नारा लगाना शुरू-शुरू किया गया था, तब भी इसका संघ-भाजपा और उनकी सरकार के आचरण में कोई प्रभाव नजर नहीं आता था। वास्तव में यह नारा, %सब का साथ% से ठीक उल्टे आचरण को ही ढांपने का काम करता था। फिर भी, कम से कम एक पर्दा तो था, जो अब पूरी तरह से गायब हो चुका है।

नितिन नबीन एक तो नये-नये और जाहिर है कि काफी अप्रत्याशित तरीके से, एक ऐसी राष्ट्रीय भूमिका में आ टपके हैं, जिसके लिए वह तैयार नहीं थे। इसलिए, उनकी बोली-बानी का संघ-भाजपा की आज की बोली से पूरी तरह से मेल नहीं बैठने में बहुत हैरानी नहीं होनी चाहिए। इसके ऊपर से उनका पूरा का पूरा राजनीतिक कैरियर उस बिहार का है, जहां संघ-भाजपा को अब भी मजबूरी में नीतीश कुमार को अपना %नेता% मानना पड़ रहा है, जिसका अर्थ उनका खुलकर सांप्रदायिक बोली का प्रयोग न कर पाना भी है। और यह स्थिति उतने ही समय से है, जितना लंबा उनका राजनीतिक कैरियर है। ऐसे में नये भाजपा अध्यक्ष का, %सब का साथ सब का विकास% का जिक्र करना, उस जगह की ही याद दिलाता है, जिसे वास्तव में संघ-भाजपा खाली कर चुके हैं।वास्तव में संघ-भाजपा 2025 के आखिर में राजनीतिक रूप से और अपनी बोली-बानी में भी, किस जगह पर पहुंच चुके हैं और इसे अभी हाल के दो प्रकरण बखूबी रेखांकित करते हैं। याद रहे कि ये दोनों प्रसंग उन राज्यों के हैं, जो अगले साल के शुरू में होने वाले विधानसभाई चुनावों के चक्र में संघ-भाजपा और उसके मोदी राज के खास निशाने पर हैं। हमारा इशारा तमिलनाडु और प. बंगाल की ओर है। पाठकों को याद ही होगा कि पिछले ही दिनों अपने बहुप्रचारित दावे में, मोदी राज में नंबर दो माने जाने वाले अमित शाह ने जोर-शोर से इसका ऐलान किया था कि इन दोनों राज्यों में अगले चुनाव में भाजपा सत्ता में आकर रहेगी। बेशक, शाह के इस ऐलान को उनका चुनावी राजनीति का जुमला मानकर छोड़ा जा सकता था, बशर्ते अपने इस दावे को जमीन पर उतारने की कोशिश में भाजपा, वह सब नहीं कर रही होती, जो वह कर रही है। और इससे भी बड़ी बात कि यह सब इतना विनाशकारी नहीं होता, जितना कि वास्तव में है।

तमिलनाडु में, जो देश के ऐसे उंगलियों पर गिने जा सकने वाले राज्यों में से एक है, जहां के लोगों के गहराई से धार्मिक होने के बावजूद, वहां सांप्रदायिक टकराव और तनाव का कोई इतिहास है ही नहीं, आने वाले विधानसभाई चुनाव की अपनी तैयारियों के हिस्से के तौर पर संघ-भाजपा ने मदुरै जिले के अंतर्गत तिरुप्परनकुंद्रम की पहाड़ी के गिर्द, एक झूठा धार्मिक विवाद और तनाव रच दिया है। यह खेल कितना कुटिलतापूर्ण और खतरनाक है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि यह विवाद खड़ा करने के लिए संघ-भाजपा ने इस स्थल को दक्षिण की अयोध्या के रूप में प्रचारित करना पहले से शुरू कर दिया था। संबंधित पहाड़ी पर तीन मंदिर हैं, एक दरगाह है जिसे सिकंदर शाह की दरगाह के नाम से जाना जाता है और कई प्राचीन जैन गुफाएं हैं। जैसा कि आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है, संघ परिवार ने दरगाह को मंदिर साबित करने का अभियान छेड़ दिया है। इसी मुहिम के हिस्से के तौर पर इस साल के शुरू में ही संघ-भाजपा ने बाहर से लोगों को लाकर, दरगाह के खिलाफ झगड़ा खड़ा करने की कोशिश की थी। बाद में इसी अभियान के हिस्से के तौर पर, एक व्यक्ति हाई कोर्ट में पहुंच गया कि पहाड़ी के मंदिर में कार्तिकाइ दीपम के नाम से बड़ी सी आग जलाने की जो पुरानी परंपरा है, उसके हिस्से के तौर पर उसे दरगाह के ठीक बगल में, दीपम करने की इजाजत दी जाए। राज्य सरकार के विरोध के बावजूद और संबंधित मंदिर के बाहर ऐसी कोई परंपरा नहीं होने के बावजूद, एक विवादों के घेरे में रहे न्यायाधीश की एकल न्यायाधीश बैंच ने, आस्था के नाम पर इस भड़काने वाली कार्रवाई की इजाजत भी दे दी।

राज्य सरकार चूंकि अपने राज्य को इससे पैदा होने वाले अनावश्यक तनाव से बचाना चाहती थी, उसके खिलाफ संघ-भाजपा ने जबर्दस्त अभियान छेड़ दिया। इस अभियान के हिस्से के तौर पर, मदुरै से सीपीआई (एम) के सांसद, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त लेखक, सू वेंकटेशन को हिंदुत्ववादी संगठनों ने हत्या की धमकियां तक देना शुरू कर दिया। और शासन ने जब इस धार्मिक स्थल के गिर्द जबरन झगड़ा करने पर आमादा संघ कार्यकर्ताओं को रोका, भाजपा के समर्थक दलों ने भी उनकी इस शरारत का समर्थन करना शुरू कर दिया। इस तरह संघ-भाजपा को तमिलनाडु में, जहां उनके पास सांप्रदायिक तनाव और ध्रुवीकरण का कोई स्थानीय मुद्दा नहीं था, ऐसा मुद्दा मिल गया। यही तो संघ-भाजपा की सफलता की राह है! साफ है कि भाजपा को एक ऐसे राज्य में भी जहां सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोई परंपरा नहीं है, बहुसं यकवादी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के बहाने गढ़ने में कोई हिचक नहीं है। दूसरा प्रसंग प. बंगाल का है, जो एक और ऐसा राज्य है जहां संघ-भाजपा अपनी सारी कोशिशों के बावजूद, अब तक सत्ता तक पहुंचने में कामयाब नहीं हुए हैं। सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के निलंबित विधायक, हुमायूं कबीर की अपने इलाके में बाबरी मस्जिद बनाने की घोषणा को, संघ-भाजपा ने बिना जरा भी समय गंवाए जवाबी सांप्रदायिक गोलबंदी का बहाना बना लिया। हिंदुत्ववादी संगठनों के नाम पर, लेकिन संघ-भाजपा के प्रत्यक्ष समर्थन से, ब्रिगेड परेड मैदान में कई लाख लोगों के कथित सामूहिक गीता पाठ% के आयोजन का ऐलान कर दिया गया और एक लाख से ज्यादा लोगों के साथ ऐसा आयोजन किया भी गया। जैसा कि आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है, यह कोई धार्मिक आयोजन न होकर वास्तव में बुनियादी तौर पर मुस्लिम-विरोधी भावनाएं भड़काने वाला आयोजन भर था। संघी राज्यपाल तक इस आयोजन में जा पहुंचे। इस आयोजन के मूल चरित्र का अंदाजा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि मैदान के बाहर ही चिकन पैटिस बेच रहे एक मुस्लिम फेरीवाले को पीट-पीटकर बुरी तरह से घायल कर दिया गया। और जब इस हमले के दोषियों को, जिन्हें पुलिस ने भी लगता है कि जान-बूझकर बहुत हल्की धाराओं में ही गिर तार किया था, अदालत ने जमानत पर छोड़ दिया, भाजपा के शीर्ष नेताओं ने सार्वजनिक रूप से उनका ऐसा सार्वजनिक अभिनंदन किया, जैसे वे राष्ट्र के लिए कोई बहुत भारी कुर्बानी देकर आये हों। बेशक, हमने यहां दो ही उदाहरण दिए हैं, जबकि भाजपा के सीधे सांप्रदायिकता भड़काने में लिप्त होने और खुल्लमखुल्ला सांप्रदायिक बोली बोलने के इसी महीने के दर्जनों उदाहरण दिए जा सकते हैं। लेकिन, इन दो उदाहरणों से ही स्पष्ट है कि संघ और उसकी राजनीतिक बाजू के रूप में भाजपा, अपने चुनावी प्रभाव का विस्तार करने के लिए, बेशरमी से सांप्रदायिक खेल खेलने और बोली बोलने के ही आसरे हैं। और इसमें अब उन राज्यों का नंबर आ रहा है, जो अब तक संघ-भाजपा के राजनीतिक नियंत्रण से और इसलिए सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से भी किसी हद तक बचे रहे थे। अगर चुनाव के महीनों पहले यह खुला सांप्रदायिक खेल खेला जा रहा है, तो चुनाव प्रचार में और चुनाव के समय क्या होगा, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। अपने दूसरे जन्म के समय की गांधीवादी-समाजवाद की बोली-बानी के बाद, एक सर्वधर्म समानता में विश्वास करने वाली पार्टी होने का दिखावा तो भाजपा ने तभी छोड़ दिया था, जब बाबरी मस्जिद-विरोधी अभियान के साथ पर्दे के पीछे से खेलने के बाद, 1988 में पालमपुर की अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भाजपा ने, बाबरी मस्जिद हिंदुओं को सौंपे जाने की औपचारिक रूप से मांग की थी।

भाजपा में कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति के निहितार्थ

अनिल जैन

गौरतलब यह भी है कि भाजपा के संविधान में कार्यकारी अध्यक्ष पद का कोई प्रावधान नहीं है। अलबत्ता पार्टी में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अंतरिम व्यवस्था के तौर पर कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किए जाने की परंपरा है, जिसके मुताबिक खुद जेपी नड्डा भी 2019 में कार्यवाहक अध्यक्ष बनाए गए थे और बाद में उन्हें पूर्णकालिक अध्यक्ष घोषित कर दिया गया था।

भारतीय जनता पार्टी में कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर बिहार के एक नेता नितिन नवीन की जिस तरह से नियुक्ति हुई है, उससे पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश जेपी नड्डा की यह बात एक बार फिर सच साबित हुई है कि %भाजपा अब हर मामले% में सक्षम और आत्मनिर्भर हो चुकी है और उसे अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मदद या उसके मार्गदर्शन की जरूरत नहीं रह गयी है।% जेपी नड्डा ने यह बात पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान साल 20 मई, 2024 को इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में कही थी। हालांकि लोकसभा चुनाव में संघ हमेशा की तरह भाजपा के लिए सक्रिय था, फिर भी भाजपा की %400 पार% की हसरत पूरी नहीं हो सकी थी। वह बहुमत से दूर रही थी और उसे सरकार बनाने के लिए करीब डेढ दर्जन छोटे-बड़े क्षेत्रीय दलों का सहारा लेना पड़ा।

लोकसभा चुनाव के बाद चार राज्यों- महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली और बिहार के विधानसभा चुनाव भाजपा ने जीते। ऐसा नहीं है कि इन चुनावों में संघ ने भाजपा की मदद नहीं की, लेकिन भाजपा की जीत में संघ से ज्यादा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की वह हिकमत अमली प्रभावी रही, जिसमें चुनाव आयोग, प्रशासन तंत्र, मीडिया और कुछ हद तक न्यायपालिका की भूमिका का भी शुमार रहा। इन चार राज्यों में मिली जीत से जेपी नड्डा की बात सही साबित हुई।

सब जानते हैं कि नड्डा पार्टी अध्यक्ष जरूर हैं लेकिन सर्वशक्तिमान अध्यक्ष नहीं। पार्टी अध्यक्ष की हैसियत से वे वही कहते और करते हैं, जैसा उन्हें निर्देशित किया जाता है। इसलिए यह आसानी से समझा जा सकता है कि अब संघ की जरूरत नहीं है और भाजपा आत्मनिर्भर हो चुकी है- जैसी इतनी बड़ी बात उन्होंने किसके इशारे पर कही होगी।

दरअसल भाजपा के 45 साल के इतिहास में अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी के बाद सिर्फ अमित शाह ही ऐसे अध्यक्ष हुए हैं जिन्हें सर्वशक्तिमान कहा जा सकता है। उनके अलावा अध्यक्ष रहे मुरली मनोहर जोशी, कुशाभाऊ ठाकरे, जना कृष्णमूर्ति, बंगारू लक्ष्मण, वेंकैया नायडू, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी में से कोई वाजपेयी-आडवाणी का तो कोई संघ का रबर स्टैंप ही रहा। हालांकि वाजपेयी और आडवाणी के फैसलों पर भी संघ की कम-ज्यादा छाप हुआ करती थी। संघ की छाप कुछ समय अमित शाह के फैसलों पर भी रही लेकिन वह धीरे-धीरे खत्म होती गई। पांच साल तक पार्टी अध्यक्ष रहने के बाद जब अमित शाह केंद्र सरकार में गृह मंत्री बने तो उनकी जगह जेपी नड्डा अध्यक्ष बनाए गए, जो अभी बने हुए हैं।

वैसे जेपी नड्डा का कार्यकाल लगभग दो साल पहले खत्म हो चुका है। वे केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं लेकिन उनकी जगह नया अध्यक्ष इसलिए नहीं बनाया जा सका है क्योंकि संघ और मोदी-शाह के बीच नए अध्यक्ष को लेकर किसी नाम पर सहमति नहीं बन पा रही है। मोदी-शाह अध्यक्ष पद पर ऐसे व्यक्ति को बैठाना चाहते हैं जो नड्डा की तरह उनका फरमानबरदार रहे, जबकि संघ चाहता है कि नया अध्यक्ष मोदी की छाया से मुक्त होकर उसके निर्देशन में काम करे।

बहरहाल इसी खींचतान के चलते बिहार के युवा नेता नितिन नवीन को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। यह फैसला शुद्ध रूप से मोदी-शाह का है, जिसे पार्टी महासचिव अरुण सिंह ने एक प्रेस विज्ञप्ति में संसदीय बोर्ड का फैसला बताया है। यह फैसला लेने के लिए संसदीय बोर्ड की बैठक कब और कहां हुई, इसका कोई ज़िक्र उनकी प्रेस विज्ञप्ति में नहीं है। इस बारे में भाजपा के नेताओं या प्रवक्ताओं से भी कोई सवाल नहीं कर रहा है।

टीवी चैनलों पर नव नियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन का अनर्गल गुणगान हो रहा है। जिस व्यक्ति की बिहार में ही कोई ठीक-ठाक राजनीतिक पहचान नहीं है, उसे कुशल संगठक और ऊर्जावान नेता बताया जा रहा है। पहले कभी किसी ने नहीं कहा लेकिन अब कहा जा रहा है कि बतौर प्रभारी नितिन नवीन ने छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में भाजपा को जिताने में अहम भूमिका निभाई थी।

सवाल यह भी है कि अगर नितिन नवीन इतने ही प्रभावशाली नेता हैं तो उन्हें इससे पहले बिहार में ही भाजपा का अध्यक्ष क्यों नहीं बना दिया गया? बिहार सरकार में भाजपा के दो उप मु यमंत्री हैं लेकिन नितिन नवीन को उप मु यमंत्री बनाने लायक भी क्यों नहीं समझा गया?

टीवी चैनलों पर नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने को %मोदी-शाह का मास्टर स्ट्रोक% बताते हुए कहा जा रहा है कि इससे पश्चिम बंगाल के चुनाव में भाजपा को बड़ा फायदा हो सकता है, क्योंकि नितिन नवीन कायस्थ समुदाय से आते हैं और बंगाल के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में इस समुदाय का काफी प्रभाव है। यह समुदाय बंगाल की राजनीति में पहले बहुत लंबे समय तक भारतीय क युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) का समर्थक रहा और पिछले डेढ़ दशक से मोटे तौर पर तृणमूल कांग्रेस के साथ है। कहा जा रहा है कि नितिन नवीन बंगाल के कायस्थ समुदाय को भाजपा की ओर आकर्षित कर सकते हैं। हालांकि हकीकत यह है कि बंगाल के कायस्थों का उत्तर भारत के कायस्थों से सामाजिक-सांस्कृतिक स्तर पर कोई मेल नहीं है।

बहरहाल गौरतलब यह भी है कि भाजपा के संविधान में कार्यकारी अध्यक्ष पद का कोई प्रावधान नहीं है। अलबत्ता पार्टी में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अंतरिम व्यवस्था के तौर पर कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किए जाने की परंपरा है, जिसके मुताबिक खुद जेपी नड्डा भी 2019 में कार्यवाहक अध्यक्ष बनाए गए थे और बाद में उन्हें पूर्णकालिक अध्यक्ष घोषित कर दिया गया था।

नड्डा से पहल एक बार 2001 में महज 10 दिन के लिए जना कृष्णमूर्ति कार्यवाहक बनाए गए थे। उस समय तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण एक स्टिंग ऑपरेशन में रिश्वत लेते पकड़े गए थे, जिसकी वजह से उन्हें हटा दिया गया था और उनके स्थान पर कृष्णमूर्ति को पहले कार्यवाहक अध्यक्ष और बाद में पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाया गया था। इस समय तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है। जेपी नड्डा अध्यक्ष बने हुए हैं, फिर भी उनके साथ एक कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया है। जाहिर है कि मोदी-शाह ने इस फैसले के जरिए न सिर्फ संघ को उसकी हैसियत बताई है, बल्कि मीडिया में अपने को भाजपा की राजनीति का जानकार समझने वाले उन लोगों को भी हास्यास्पद बना दिया है जो पिछले कई महीनों भाजपा अध्यक्ष पद के लिए दर्जन भर से ज्यादा नामों को दावेदार बता रहे थे।

मोदी-शाह ने इससे पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और दिल्ली में मु यमंत्री चुनने के मामले में भी ऐसा ही किया था। उन्होंने इन प्रदेशों में संघ की पसंद को दरकिनार करते हुए अपनी पसंद के मु यमंत्री बनाए। यह सही है कि इन चारों राज्यों में जिन लोगों को मु यमंत्री बनाया गया है, उन सभी का संघ से जुड़ाव है लेकिन मु यमंत्री पद के लिए वे संघ नेतृत्व की पसंद कतई नहीं हैं।

दरअसल नरेन्द्र मोदी और अमित शाह ने अपनी हनक और मीडिया प्रबंधन के जरिये अपने कद को पार्टी से भी बड़ा बना लिया है। अब उन्हें पार्टी की आवश्यकता नहीं है बल्कि वे पार्टी की जरूरत बन गए हैं।

विविध समाचार

युवाओं को विदेशों में सुरक्षित रोजगार से जोड़ेगी हिमाचल सरकार : उप–मुख्यमंत्री

शिमला। उप–मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि हिमाचल सरकार युवाओं को विदेशों में सुरक्षित रोजगार से जोड़ेगी। ऐसे समय में जब वैश्विक स्तर पर रोजगार के क्षेत्र में प्रतिस्पध ार्ा लगातार बढ़ रही है, प्रदेश सरकार ने यह सुनिश्चित करने की दिशा में निर्णायक पहल की है कि हमारे युवाओं को विदेशों में सुरक्षित, कानूनी और भरोसेमंद माध्यमों से रोजगार मिलना सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार स्वयं जिम्मेदारी लेकर युवाओं को विदेश भेजने की पूरी प्रक्रिया को व्यवस्थित और पारदर्शी बना रही है, ताकि किसी को भी ठगी, ध ोखे या असुरक्षा की स्थिति का सामना न करना पड़े। यह कदम प्रदेश सरकार की 'हर युवा को हुनर, हर हुनर को अवसर' की प्रतिबद्धता का परिणाम है। उप–मुख्यमंत्री सोमवार को पालकवाह में आयोजित हिमाचल सरकार की 'ओवरसीज रिक्रूटमेंट ड्राइव' की श्रृंखला के राज्यस्तरीय कार्यक्रम के शुभारंभ सत्र में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार युवाओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है और यह पहल उसी दिशा में एक ठोस कदम है। विदेशों में उपलब्ध विभिन्न ट्रेड्स में नौकरियों की मांग के अनुसार युवाओं का चयन किया जाएगा, ताकि कौशल और अवसर का सही समन्वय सुनिश्चित हो सके। श्री अग्निहोत्री ने कहा कि एक समय ऐसा भी था जब विदेश में रोजगार दिलाने के नाम पर लोगों से ठगी होती थी। माता–पिता अपने जीवन की गाढ़ी कमाई खर्च कर बच्चों को बाहर भेजते थे, पर अवैध ा तरीके और जालसाजी से ठगे जाते थे। अब हिमाचल सरकार ने तय किया है कि युवाओं को सुलभ, सस्ते और कानूनी तरीके से विदेश भेजा जाएगा। उप–मुख्यमंत्री ने कहा यह सरकार का सबसे सुरक्षित, कानूनी और पारदर्शी तरीका है, जिससे हिमाचल के युवा अपने कौशल के अनुरूप विदेश में रोजगार प्राप्त कर सकेंगे। विदेशों में स्किल की मांग है और हिमाचल प्रदेश के युवा इससे लाभान्वित होंगे। इस पहल से रोजगार कार्यालय की कार्यप्रणाली में नवाचार आएगा और युवाओं को हर संभव सहायता मिलेगी। श्री अग्निहोत्री ने विभाग से इस अभियान को और विस्तारित करने तथा युवाओं की हर संभव मदद सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने युवाओं से ऑनलाइन ठगी से सावधान रहने और डेटा सुरक्षा के प्रति सतर्कता बरतने का भी आह्वान किया। इस अवसर पर उन्होंने चार चयनित युवाओं को प्रोविजनल ऑफर लेटर भी प्रदान किए। यह कार्यक्रम श्रम, रोजगार एवं ओवरसीज प्लेसमेंट विभाग और राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड के संयुक्त तत्वाधध ान में आयोजित किया गया। यह इस कड़ी का दूसरा आयोजन था जिसकी 9 अक्तूबर को हमीरपुर से शुरूआत की गई थी। पालकवाह में ट्रेलर चालक के 100 पदों के लिए प्रदेश के 457 युवाओं ने भाग लिया। अभ्यर्थियों की अंग्रेजी कौशल क्षमता का परीक्षण पालकवाह सभागार परिसर एवं ड्राइविंग टेस्ट कांगड़ मैदान में लिया गया। चयनित अभ्यर्थियों को दुबई के जेबेल अली पोर्ट में नियुक्ति मिलेगी। उन्हें 2,250 यूएई दिरहम (लगभग 52,000 रुपये) मासिक वेतन, आवास, ओवरटाइम और अन्य भत्तों की सुविधा मिलेगी। कार्यक्रम में प्रदेश के श्रम आयुक्त डॉ. वीरेंद्र शर्मा ने बताया कि यह पहली बार है जब प्रदेश सरकार ने युवाओं को विदेश भेजने के लिए औपचारिक नीति बनाई है। विदेश मंत्रालय द्वारा निध ार्ारित फीस के अनुसार युवाओं को बाहर भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि विदेश में भेजे जाने वाले युवाओं को कोई कठिनाई या ठगी का सामना न करना पड़े। इसके लिए समर्पित हेल्पलाइन स्थापित की जा रही है।

राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स निगम एक सॉफ्टवेयर भी विकसित कर रहा है, जिससे युवा अपनी शिकायतें और समस्याएं सीधे साझा कर सकेंगे। इस अवसर पर जिला श्रम एवं रोजगार अधिकारी अक्षय शर्मा, एसडीएम हरोली विशाल शर्मा सहित अन्य अधिकारी और बड़ी संख्या में अभ्यार्थी और स्थानीय युवा उपस्थित रहे।

पंजाब में इमारतों की ऊंचाई 15 से बढ़ाकर 21 मीटर तक करने के लिए अब मंजूरी की जरूरत नहीं

चंडीगढ ३०/१२ (संवाददाता): मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई पंजाब कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई है। कैबिनेट ने बरनाला नगर कौंसिल को अपग्रेड करते हुए नगर निगम का दर्जा देने की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही, लुधियाना जिले में 'लुधियाना नॉर्थ' नाम से एक नई सब–तहसील बनाने के लिए भी जरूरी मंजूरी दे दी गई है। पंजाब कैबिनेट ने 'पंजाब यूनिफाइड बिल्डिंग नियम 2025' को भी हरी झंडी दे दी है। इस नए नियम के मुताबिक, पंजाब में बनने वाली नई कॉलोनियों में इमारतों की ऊंचाई 15 मीटर से बढ़ाकर 21 मीटर तक करने के लिए अब विभाग से अलग से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी। इसके लिए केवल आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेट ही काफी माना जाएगा। मंत्रिमंडल ने 'पंजाब स्पोर्ट्स मेडिसिन काडर' में लगभग 100 नई असामियां (पद) भरने की भी मंजूरी दी है। ये सभी भर्तियां तीन साल के लिए ठेके के आध ार पर की जाएंगी। इनमें ग्रुप ए की 14, ग्रुप बी की 16 और ग्रुप सी की लगभग 80 असामियां भरी जाएंगी। कैबिनेट ने केंद्र सरकार द्वारा डेरा बस्सी में 100 बेड का ईएसआई अस्पताल बनाने के लिए 4 एकड़ जमीन मुहैया कराने की भी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा, मंत्रिमंडल ने पंजाब के नशा मुक्ति केंद्रों के नियमों में भी संशोधन किया है। इस संशोधन के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा नशा मुक्ति केंद्रों में दी जाने वाली दवाइयों की देखरेख और प्रबंधन अब सीधे पंजाब सरकार द्वारा किया जाएगा।

आप विधायक लालपुरा को हाईकोर्ट से झटका, सजा पर नहीं लगेगी रोक

चंडीगढ ३०/१२ (संवाददाता):पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से आज आप विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा को करारा झटका लगा है। विधायक ने खुद को हुई चार साल की सजा पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सजा पर रोक से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि चूंकि उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द करने के लिए अभी तक कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई है, इसलिए इस समय तत्काल हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं लगती। विध ायक लालपुरा के वकील ने दलील दी कि अगर सजा पर रोक नहीं लगाई गई, तो उनकी विधानसभा सदस्यता स्वतः ही रद्द हो जाएगी, जिसके लिए उनके निर्वाचन क्षेत्र में नए सिरे से चुनाव कराने होंगे। कोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए पूछा कि जब रद्द करने जैसे कदम उठाए ही नहीं गए, तो इतनी जल्दबाजी क्यों? हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई अगले महीने के लिए स्थगित कर दी और राज्य सरकार को अगली तारीख पर पूरे मामले का रिकॉर्ड कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया।

अकाली कार्यकर्ताओं के खिलाफ झूठे केस दर्ज कर आप ने अपनी हार स्वीकार की : हरसिमरत कौर बादल

तरनतारण। वरिष्ठ अकाली नेता सरदारनी हरसिमरत कौर बादल ने आज कहा कि आम आदमी पार्टी ने तरनतारण उपचुनाव में अकाली दल के उम्मीदवार की बेटी कंचनप्रीत कौर और अन्य अकाली नेताओं के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कर अपनी हार स्वीकार कर ली है।

यहां पार्टी उम्मीदवार प्रिंसिपल सुखविंदर कौर रंध ावा के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए बठिंडा की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने लोगों से अपील की कि वे "ध ार्मी फौजी" के परिवार का समर्थन करें, जो समाज सेवा के लिए दृढ़ संकल्पित है। वहीं दूसरी ओर "गद्दार" और आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार हरमीत सिंह संधू है, जो प्रचार वाली गाड़ियों से लटककर सत्ता में आने का सपना देख रहा है। अकाली नेता ने जोर देकर कहा कि दिल्ली आधारित सभी पार्टियाँ एकजुट होकर अकाली दल के खिलाफ खड़ी हैं।

उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अपनी क्षेत्रीय पार्टी का समर्थन कर पंजाब विरोध ी ताकतों को स्पष्ट संदेश दें, जो अपने स्वार्थी राजनीतिक हितों के लिए पंजाबियों को बाँटने पर तुली हुई हैं।

उन्होंने कहा, "मैं आपसे अपील करती हूँ कि आप चुनाव लड़ रही सभी पार्टियों का मूल्यांकन करें। आपने देखा है कि पिछली कांग्रेस सरकार किसानों का कर्ज माफ करने के अपने वादे से मुकर गई।

आम आदमी पार्टी की सरकार किसानों को मुआवजा और युवाओं को रोजगार देने से इनकार कर चुकी है, जबकि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति आपके सामने है।" हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि तरनतारण उपचुनाव की लड़ाई सच और झूठ के बीच लड़ाई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने लगातार जनता के साथ धोखा किया है। हाल ही में आई विनाशकारी बाढ़ के दौरान भी इनमें से कोई पार्टी जनता की मदद के लिए नहीं उतरी।

उन्होंने कहा कि सिर्फ अकाली दल ही किसानों की सहायता के लिए आगे आया और एक लाख एकड़ भूमि के लिए प्रमाणित गेहूं के बीज उपलब्ध करवा रहा है। बठिंडा की सांसद ने यह भी बताया कि किस तरह आम आदमी पार्टी ने पंजाब की महिलाओं से झूठे वादे किए और फिर कहा कि सभी महिलाएं आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधियों से कहें कि वे वोट मांगने से पहले उनके खातों में घ45,000 जमा करवाएं, क्योंकि उन्होंने चार साल पहले घ1,000 प्रति माह देने का वादा किया था। हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि अकाली दल ने अपनी सरकार के समय सीमावर्ती क्षेत्र में अनेक विकास योजनाएँ लागू की थीं। पार्टी ने ही बार्डर फेंस के पार खेती करने वाले किसानों को मुआवजा दिया था।

उसी ने लिंक सड़कों का जाल बिछाया, मंडियाँ बनवाईं और आटा–दाल, समाज कल्याण योजनाएँ शुरू कीं।

उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने इन सभी योजनाओं को या तो बंद कर दिया है या इनमें भारी कटौती कर दी है, जिससे समाज के गरीब और वंचित वर्ग को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

इस मौके पर वरिष्ठ नेता गुरचरण सिंह ग्रेवाल, बीबी कंचनप्रीत कौर, परमबंस सिंह रोमाणा, गौरव वल्टोहा, परमजीत ढिल्लों, मक्खन लालका, गुरसेवक सिंह शेख और गगनदीप सिंह खंडेबाद मौजूद थे।

समाजवादी आंदोलन के जनक आचार्य नरेंद्रदेव

भारतीय समाजवादी आंदोलन के तीन प्रमुख स्तम्भ आचार्य नरेन्द्र देव, डॉ. राम मनोहर लोहिया और जय प्रकाश नारायण ने समाजवाद की जड़ों को भारत में गहराई तक पहुंचाने में अपनी महती भूमिका निभाई। इनकी अमिट छाप जनमानस पर ऐसी पड़ी कि भले ही आज समाजवादी आंदोलन के संगठन एकजुट नहीं हैं फिर भी इन नेताओं की व्यक्तिगत ऊर्जा समय–समय पर समाजवाद को जागृत करती रही हैं। आचार्य नरेन्द्र देव का जन्म 31 अक्टूबर 1889 को सीतापुर (उ.प्र.) में हुआ था। इनके पिता बाबू बलदेव प्रकाश पेशे से वकील थे और इन्हें विरासत में अपने पिता से भारतीय संस्कृति व साहित्य मिले। इनके घर जाने माने साहित्यकारों का आना–जाना था। दे शेर कथा नामक प्रसिद्ध बंगाली पुस्तक का हिन्दी में अनुवाद करने वाले प्रसिद्ध लेखक माधव प्रसाद ने इनका नाम अविनाशी लाल से बदलकर नरेन्द्र देव रखा था। आचार्य नरेन्द्र देव पर स्वामी रामतीर्थ के प्रवचनों का खासा असर पड़ा था, जिससे उन्होंने बचपन में ही रामायण, महाभारत, बेताल पच्चीसी, सिंहासन बत्तीसी, चन्द्रकान्ता, सूरसागर व गीता का गहराई से अध्ययन किया। आचार्य नरेन्द्र देव भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन में अपने पिता के साथ प्रथम बार 1905 में बनारस में कांग्रेस अधिवेशन में हिस्सा लेने पहुंचे थे। मैट्रिक पास करने के पश्चात् जब वे बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में पढने गये तो इनका परिचय महामना मदनमोहन मालवीय से हुआ, लेकिन बाद में जैसे ही कांग्रेस का विभाजन हुआ तो नरेन्द्र देव तिलक और विपिन चन्द्र पाल की ओर आकृष्ट होकर उनके सानिध्य में कार्य करने लगे। जब लोकमान्य तिलक ने कलकत्ता में एक नयी पार्टी की स्थापना की तो आचार्य नरेन्द्र देव के हिन्दी भाषण से वे बहुत प्रभावित हुए। कलकत्ता अधिवेशन के बाद जब नरेन्द्र देव इलाहाबाद लौटे तो इनका भव्य स्वागत किया गया। सन् 1913 में एम.ए. और 1915 में एल.एल.बी. करने के बाद वे भी वकालत करने लगे। कांग्रेस ने जब परिषदों का बहिष्कार किया तो तिलक के अनुयायी होने के नाते इन्होंने इस बहिष्कार को सफल बनाने के लिए जी–जान से कार्य किया। नागपुर अधिवेशन में असहयोग आन्दोलन का प्रस्ताव स्वीकार होने पर, वकालत छोड़ दी और राष्ट्रीय कार्यों में जुट गये। पंडित नेहरू ने उन्हें फैजाबाद छोड़कर बनारस में काशी विद्यापीठ का कार्यभार सौंपा। 1926 में डॉ. भगवानदास के त्याग पत्र देने के बाद इन्हें विद्यापीठ का अध्यक्ष बनाया गया। भगवानदास के पुत्र ने इनके नाम के आगे आचार्य शब्द जोड़ दिया। आचार्य नरेन्द्र देव ने, बौद्धधर्म को बखूबी पढ़कर मार्क्सवाद के गहन अध्ययन के पश्चात् एक ऐसा मानस तैयार किया कि वे भारत के जाने–माने नेता के रूप में प्रतिष्ठित हो गये। उनके पुराने व नवीन विचारों के संगम के कारण वे कांग्रेस में समाजवादी विचारों वाले धड़े के निर्विवाद नेता मान लिये गये। पटना में मई 1934 को वे कांग्रेस समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष चुने लिये गये। यहीं से भारत में समाजवादी विचारध ारा का उदय हुआ और यह विचारधारा इतनी तीव्रगति से पूरे देश में फैली कि आम जन–जीवन इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहा। आचार्य नरेन्द्र देव ने अपनी समाजवादी विचारधारा में शनिरन्तर बढ़ते जाना ही संस्कृति का मूलाधार हैश को अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता पर बल दिया। उनका मत था कि हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि जीवन के साथ–साथ संस्कृति भी बदलती है। हमारा जीवन स्थिर और जड़ नहीं है। समाज के आर्थिक और सामाजिक जीवन में परिवर्तन होते रहते हैं और यहीं से सांस्कृतिक जीवन मूल्य भी बदलते हैं। आचार्य नरेन्द्रदेव ने मजहब से ऊपर राष्ट्रीयता की भावना को बल दिया। उन्होंने परिवर्तन का अर्थ कदापि यह नहीं माना कि, अतीत के अंश जो उत्कृष्ट और जीवनप्रद है, उनकी रक्षा नहीं करनी चाहिए। लेकिन नये मूल्यों का नरेन्द्र देव ने सदैव स्वागत किया तथा अनावश्यक आचार व्यवहार जो कि समाज व राष्ट्र के लिए हानिकारक है, उनका परित्याग करने पर भी जोर दिया। समाजवादी विचारधारा में परिवर्तन अवश्यंभावी है और हमें नये जीवन के लिए उद्देश्य स्थिर करने होंगे। हमारी संस्कृति सर्वोच्च है और इसमें वे सभी तथ्य व तत्व मौजूद हैं, जिससे नवयुग और नवसमाज का निर्माण हो सकेगा। समाजवादी नेताओं में आचार्य नरेन्द्र देव के प्रति अगाध श्रद्धा थी।

इसका संजीदा उदाहरण लोकनायक जयप्रकाश नारायण के उस पत्र से झलकता है, जिसमें उन्होंने लिखा था कि मेरा मन रो रहा है, कि, आपको क्या लिखूं? अगर हमें यह पता होता कि आप किसान मजदूर पार्टी और समाजवादी दल के विलय की बात से नाराज हैं तो हम ऐसा हरगिज नहीं करते। इस विलय से आचार्य नरेन्द्रदेव को इसलिये धक्का लगा कि विलय से समाजवादी पार्टी का मार्क्सवादी चरित्र नष्ट हो जायेगा। 1948 में जब आचार्य नरेन्द्र देव और डॉ. लोहिया ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी, तब भी वे इस मत के थे कि, हमें कांग्रेस को नहीं छोडना था, परन्तु यह पार्टी के बहुमत का फैसला था, जिसे इन्होंने ध्यान रखकर पुनरू कांग्रेस की ओर मुड़कर नहीं देखा। हालांकि पार्टी में कई संकट आये और विभाजन भी होता रहा। ट्रावनकोर कोचीन में जब प्रथम समाजवादी पार्टी की सरकार ने पुलिस द्वारा प्रदर्शन करने वालों पर गोली चलवाई जिसमें चार आदमी मारे गये, तब डॉ. लोहिया ने अपनी ही सरकार के मुख्यमंत्री से त्याग–पत्र मांग लिया था। तब पार्टी महामंत्री होने के कारण इनका कड़ा विरोध ा हुआ और अंततरू पार्टी के नागपुर सम्मेलन में डॉ. लोहिया से इस्तीफा मांगा गया, समाजवादी विचारधारा वाले दल के इस कार्य का मलाल आचार्य नरेन्द्र देव को अन्त तक रहा। समाजवादी पार्टी इससे दो गुटों में विभाजित हो गयी। लेकिन आपातकाल के बाद बनी जनता पार्टी में इसका विलय हो गया। जनता सरकार टूटने के बाद समाजवादी अलग–अलग पार्टियों में बिखर गये और अब तो यह आन्दोलन प्रायरू खत्म सा ही लगता है। आज नेता राष्ट्र में समाजवाद की बातें अवश्य करते हैं, लेकिन सच तो यह है कि जिन नेताओं ने समाजवाद के जरिये देश की दशा व दिशा बदलने का प्रयास किया, वे अब रह नहीं गये, बल्कि उनके बाद जिनके हाथों में इस आन्दोलन की डोर आयी वे सत्ता से समझौता कर बैठे।

Printed, Published,Edited, & Owned by Prakash Kumar Dhal, Printed at Promodini Publication, Main road , Chhend colony , Rourkela-15 & Published at ECR-73, Chhend Colony, Rourkela-15, Editor : Prakash kumar Dhal, Email:kalingasamachar@gmail.com , Mob: 9439951525, Ph. 0661-2646999

ओडिशा समाचार

कलिंग समाचार | राउरकेला, बुधवार 31 दिसंबर 2025 | पृष्ठ-6

42 प्रदूषण जांच केंद्रों के लाइसेंस रद्द

भुवनेश्वर ३०/१२ (संवाददाता): ओडिशा में प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्रों (पीयूसीसी) की बढ़ती मांग ने अनजाने में ही अवसरवादियों की एक नई नस्ल को जन्म दे दिया है। इस मांग में तेजी से मुनाफा कमाने का अवसर देखकर कई लोगों ने घर-घर जाकर या सड़क किनारे सुविधाजनक प्रमाणन देने के लिए मोबाइल टेस्टिंग वैन चलाना शुरू कर दिया। हालांकि, इस सुविधा की भारी कीमत उन्हें अवैधता के रूप में चुकानी पड़ी, ज़्योंकि इनमें से कई इकाइयां त्वरित लाभ के लिए वास्तविक उत्सर्जन परीक्षणों को दरकिनार करती पाई गईं।

इस बढ़ती समस्या के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए, ओडिशा परिवहन विभाग ने धोखाधड़ी के रूप में पहचाने गए 42 प्रदूषण परीक्षण केंद्रों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। कार्यप्रणाली जांच में पता चला कि ये केंद्र प्रमाणपत्र प्राप्त करने के इच्छुक वाहन मालिकों की भारी संज़्या का फायदा उठा रहे थे। सज़्त उत्सर्जन जांच करने के बजाय, ये संचालक फर्जी प्रमाणपत्र जारी कर रहे थे। कई मामलों में, विभाग ने पाया कि केंद्र ओडिशा के बाहर स्थित स्थानों से संचालित हो रहे थे, जबकि वे राज्य के भीतर पंजीकृत वाहनों के लिए प्रमाणपत्र जारी कर रहे थे-जो क्षेत्रीय परिवहन प्रोटोकॉल का स्पष्ट उल्लंघन है। सरकारी प्रतिक्रिया और साइबर जांच अतिरिक्त परिवहन आयुक्त दीप्तिरंजन पात्रा ने रद्द किए जाने की पुष्टि करते हुए कहा कि यह कार्रवाई धोखाधड़ी के ठोस सबूतों के आधार पर की गई है। व्यवस्था की गहन जांच सुनिश्चित करने के लिए परिवहन आयुक्त अमिताभ ठाकुर ने भुवनेश्वर के साइबर पुलिस स्टेशन में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। इस कदम का उद्देश्य केंद्रीय वाहन डेटाबेस में डिजिटल हेरफेर की जांच करना है, जिसमें कथित तौर पर फर्जी परीक्षा परिणाम अपलोड करने के लिए छेड़छाड़ की गई थी। डेटा विसंगति चुनौतियाँ इस कार्रवाई से डेटा में भारी कमी भी उजागर हुई। विभाग के अधिकारियों के अनुसार, राज्य में लगभग 50 से 60 लाख वाहनों का प्रदूषण डेटा वर्तमान में पुराना है या केंद्रीय डेटाबेस में अपडेट नहीं किया गया है। इस तालमेल की कमी के कारण अधिकारियों के लिए उत्सर्जन मानदंडों को प्रभावी ढंग से लागू करना मुश्किल हो गया है, जिससे धोखाधड़ी करने वाले ऑपरेटर बच निकलने में कामयाब हो रहे हैं।

सार्वजनिक परामर्श में सी-सेज़्शन के 15 महीने बाद महिला के पेट में सर्जिकल कपड़ा मिला परिवहन विभाग ने नागरिकों से सतर्क रहने और बिना उचित जांच के तत्काल प्रमाण पत्र देने का वादा करने वाली अनधिकृत मोबाइल वैन का उपयोग न करने का आग्रह किया है। जिन वाहन मालिकों को गलत प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं या चालान संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उनकी सहायता के लिए एक टोल-फ्री हेल्पलाइन (1800-345-1073) शुरू की गई है। यह प्रवर्तन अभियान राज्य की एक व्यापक पहल का हिस्सा है जिसका उद्देश्य पीयूसीसी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और यह सुनिश्चित करना है कि ओडिशा की सड़कों पर केवल वास्तविक, पर्यावरण के अनुकूल वाहन ही चलें। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि आगे की जांच जारी है और आने वाले हज़्तों में और भी लाइसेंस रद्द किए जा सकते हैं।

राउरकेला इस्पात संयंत्र में मध्य-स्तरीय अधिकारियों हेतु दो दिवसीय सॉफ्ट स्किल्स प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित

राउरकेला ३०/१२ (संवाददाता): राउरकेला इस्पात संयंत्र के ज्ञानार्जन एवं विकास विभाग में मध्य-स्तरीय अधिकारियों के लिए अमूर्त कौशल (सॉज़्ट स्किल्स) पर आधारित दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बोकारो इस्पात संयंत्र के पूर्व कार्यपालक निदेशक (कार्मिक एवं प्रशसन), डॉ. एस एन सिंह ने विशेषज्ञ प्रशिक्षक के रूप में सत्रों का सञ्चालन किया ढ्ढ मुज़्य महाप्रबंधक (एचआर-एलएंडडी), श्री पी के साहू एवं महाप्रबंधक (एचआर- एलएंडडी), श्री एम के अग्रवाल ने भी उद्घाटन सत्र में उपस्थित होकर प्रतिभागियों को संबोधित किया इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में संयंत्र के विभिन्न विभागों से कुल 19 अधिकारियों ने भाग लिया।

इस प्रशिक्षण का उद्देश्य मध्य-प्रबंधन स्तर पर व्यावसायिक दक्षताओं को सुदृढ़ करने के लिए संचार कौशल, टीमवर्क, पारस्परिक प्रभावशीलता, नेतृत्व अभिमुखता तथा व्यवहारिक कौशलों को सशक्त बनाना था।सत्रों के दौरान कार्यस्थल पर सहयोग एवं नेतृत्व की तत्परता को बढ़ाने के उद्देश्य से संवादात्मक गतिविधियाँ, आत्ममंथन अज़्यास तथा केस-आधारित चर्चाएँ आयोजित की गईं, जिससे प्रतिभागियों को अपने दैनिक व्यावसायिक कार्यों में प्राप्त सीख को प्रभावी रूप से लागू करने में सहायता मिले। श्री एम. के. अग्रवाल ने कार्यक्रम का समन्वय किया।

रथ यात्रा 2026 से पहले रत्न भंडार की पूरी इन्वेंट्री की जाएगी

भुवनेश्वर ३०/१२ (संवाददाता): कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने रविवार को कहा कि पुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार (खजाने) की लंबे समय से इंतज़ार की जा रही इन्वेंट्री रथ यात्रा 2026 से पहले की जाएगी। SOP फाइनल स्टेज में, हाई-लेवल पैनल सरकार की मंजूरी के लिए गाइडलाइन जमा करेगा मंत्री ने बताया कि देवताओं की कीमती चीज़ों की गिनती के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अपने फाइनल स्टेज में है और इस पर एक हाई-लेवल कमेटी की मीटिंग में डिटेल में चर्चा की गई है। कमेटी जल्द ही मंजूरी के लिए राज्य सरकार को स्ह्क्क जमा करेगी, जिसके बाद इन्वेंट्री प्रोसेस शुरू होगा।

रीति-रिवाजों और पज़्लिक दर्शन का सज़्मान करने के लिए इन्वेंट्री हरिचंदन ने कहा कि कमेटी ने यह पक्का करने का फैसला किया है कि गिनती का काम मंदिर की रीति-रिवाजों या पज़्लिक दर्शन में रुकावट डाले बिना किया जाए। इस प्रोसेस के दौरान भक्तों को नटमंदिर में मौजूद बहारकथा (बाहरी एरिया) से दर्शन करने की इजाज़त होगी। तीन-फेज़ में गिनती का प्रोसेस प्लान किया गया है सूत्रों के मुताबिक, रत्न भंडार मॉनिटरिंग कमेटी ने 11 पेज की एक गाइडलाइन तैयार की है जिसमें तीन-फेज़ में इन्वेंट्री प्रोसेस की जानकारी दी गई है। पहले फेज़ में, देवताओं द्वारा रेगुलर इस्तेमाल किए जाने वाले गहनों की गिनती की जाएगी। इसके बाद रत्न भंडार के बाहरी चैंबर और फिर अंदर के चैंबर में रखी कीमती चीज़ों की इन्वेंट्री की जाएगी।गिनती एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से की जाएगी ताकि रोज़ाना के कामों में कोई रुकावट न आए। सेवकों के पास ड्ढष्ठ कार्ड होंगे, अटेंडेंस लिस्ट रखी जाएगी बढ़ी हुई सिज़्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी के उपायों के तहत, इन्वेंट्री प्रोसेस में लगे सेवकों को आइडेंटिटी कार्ड दिए जाएंगे। गिनती के दौरान मौजूद लोगों की एक डिटेल्ड लिस्ट भी तैयार की जाएगी और उसे मेंटेन किया जाएगा। RBI के अधिकारी हिस्सा लेंगे, प्रोसेस की वीडियोग्राफी की जाएगी इस काम की क्रेडिबिलिटी को और बढ़ाने के लिए, रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने इन्वेंट्री प्रोसेस में हिस्सा लेने के लिए दो अधिकारियों को नॉमिनेट किया है। अंदर के चैंबर की कीमती चीज़ों की रोज़ाना गिनती के बाद, चाबियां डिस्ट्रिज़्ट ट्रेजरी में जमा कर दी जाएंगी। पूरी इन्वेंट्री प्रोसेस की वीडियोग्राफी की जाएगी, और कैमरा चिप्स को सुरक्षित रखा जाएगा। इसके अलावा, सभी गहनों को डिजिटाइज़ किया जाएगा और 1978 में तैयार की गई मौजूदा इन्वेंट्री लिस्ट से क्रॉस-वेरिफाई किया जाएगा, ताकि सटीकता और ऐतिहासिक निरंतरता सुनिश्चित हो सके। इस कदम को पवित्र मंदिर के अनमोल खजानों की पारदर्शिता और व्यवस्थित डॉज़्यूमेंटेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है।

रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस में ट्रैफिक ई-चालान के कैश पेमेंट की अनुमति दी

भुवनेश्वर ३०/१२ (संवाददाता): ओडिशा की स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने सभी रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर को ट्रैफिक नियम तोड़ने पर गाड़ी चलाने वालों को दिए गए ई-चालान के बदले कैश पेमेंट लेने का निर्देश दिया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। यह कदम गाड़ी मालिकों की शिकायतों के बाद उठाया गया है, जिसमें कहा गया था कि उन्हें वन-टाइम पासवर्ड न मिलने और सिस्टम से जुड़े मोबाइल नंबर बदलने जैसी दिक्कतों की वजह से ऑनलाइन फाइन भरने में दिक्कत हो रही थी। नए इंतज़ाम के तहत, RTO ऑफिस में ई-चालान पेमेंट लेने के लिए एक तय ऑफिसर ज़िम्मेदार होगा। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के एक ऑफिसर ने बताया कि सिर्फ़ गाड़ी मालिक या डिफॉल्टर ही एज़्टिव ई-चालान ड्यूज़ का पेमेंट कर पाएंगे। ई-चालान मिलने के बाद, एक मनी रसीद दी जाएगी और पेमेंट भी ऑनलाइन अपडेट कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ई-चालान के लिए मिला पैसा अगले वर्किंग डे पर सरकारी खजाने में जमा कर दिया जाएगा।

ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का बयान, फरवरी से गाड़ियों के लिए ग्रीन स्टिकर्स ज़रूरी

भुवनेश्वर ३०/१२ (संवाददाता): ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बिभूति जेना ने शनिवार को कहा कि ओडिशा अगले साल फरवरी से मोटर व्हीकल एज़्ट के तहत ग्रीन स्टिकर और वैलिड पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट को लागू करने के लिए सज़्त कदम उठाएगा। जेना ने कहा, मोटर व्हीकल एज़्ट के तहत एक वैलिड PUCC, इंश्योरेंस और फिटनेस सर्टिफिकेशन ज़रूरी हैं। उन्होंने कहा कि ये नियम लंबे समय से हैं, और यह चिंता की बात है कि लोग अब घबरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि PUCC जारी करने के सिस्टम का रिव्यू किया जाएगा ताकि यह पक्का हो सके कि सर्टिफिकेट ठीक से जारी किए जाएं।जेना ने कहा कि अधिकारी मॉनिटरिंग सिस्टम को मजबूत करने और ओवरऑल कज़्प्लायंस को बेहतर बनाने के लिए इस मुद्दे की डिटेल में जांच करेंगे। यहां यह बताया जा सकता है कि इससे पहले 20 दिसंबर को स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने कहा था कि राज्य में बिना वैलिड PUCC वाली गाड़ियों को पेट्रोल और डीजल सप्लाई नहीं किया जाएगा। स्ज्ञ ने राज्य में रिटेल आउटलेट चलाने वाली ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को निर्देश दिया था कि वे 1 जनवरी के बाद उन गाड़ियों को ज़्यूल देने से सज़्ती से मना करें जिनके पास वैलिड पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है। हालांकि, बाद में स्ज्ञ ने अपने आदेश को 1 फरवरी, 2026 तक के लिए टाल दिया। यह फैसला पॉल्यूशन टेस्टिंग स्टेशनों पर बहुत ज़्यादा भीड़ और टेज़्निकल दिक्कतों की रिपोर्ट आने के बाद लिया गया।

राउरकेला इस्पात संयंत्र में 'परिसंपज़ियों एवं कार्मिकों की सुरक्षा, इंडज़्शन फर्नेस में सुरक्षित कार्य' विषय पर कार्यक्रम आयोजित

राउरकेला ३०/१२ (संवाददाता): राउरकेला इस्पात संयंत्र (आरएसपी) के सीपीटीआई में 'परिसंपज़ियों एवं कार्मिकों की सुरक्षा- इंडज़्शन फर्नेस में सुरक्षित कार्य' विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन ओडिशा सरकार के कारखाना एवं बॉयलर निदेशालय, राउरकेला मंडल द्वारा सेल आरएसपी तथा रुंगटा कमंडा स्टील प्लांट के सहयोग से किया गया। कार्यपालक निदेशक (खान विकास-सीएमएलओ), आरएसपी श्री बिपिन कुमार गिरी ने उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता की। मंचासीन अतिथियों में उप निदेशक, कारखाना एवं बॉयलर, ओडिशा सरकार; श्री बिभू प्रसाद, सहायक निदेशक, कारखाना एवं बॉयलर, ओडिशा सरकार के श्री सुवेन्दु शेखर राउत एवं श्री स्वराज त्रिपाठी, मुज़्य महाप्रबंधक (सुरक्षा एवं अग्निशमन सेवाएं), श्री हीरालाल महापात्र शामिल थे। अन्य विशिष्ट अतिथियों में महाप्रबंधक (सुरक्षा), श्री अबाकास बेहरा तथा सचिव (एनएससी-ओडिशा शाखा), श्री एम मोहिनी उपस्थित थे। कार्यक्रम में सुंदरगढ़ जिले की विभिन्न औद्योगिक इकाइयों से लगभग 80 प्रतिनिधियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। अपने उद्घाटन संबोधन में श्री गिरी ने इंडज़्शन फर्नेस जैसे खतरों से भरे कार्यस्थल में सुरक्षित कार्य पद्धति को सुदृढ़ करने हेतु इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन के लिए कारखाना एवं बॉयलर निदेशालय, ओडिशा सरकार के प्रयासों की सराहना की। श्री बिभू प्रसाद ने ओडिशा में औद्योगिक सुरक्षा मानकों को सुदृढ़ करने के लिए सक्रिय उपाय अपनाने, कार्मिकों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करने तथा व्यापक जागरूकता सृजित करने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री सुवेन्दु शेखर राउत ने उपस्थितजनों का स्वागत किया तथा विभिन्न औद्योगिक सुरक्षा नियमों पर प्रकाश डाला। वहीं श्री स्वराज त्रिपाठी ने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित किया। तकनीकी सत्रों का संचालन आरएसपी, ओरिटेक सॉल्यूशंस, महावीर फेरो एलॉयज तथा रुंगटा कमंडा स्टील प्लांट के उद्योग विशेषज्ञों द्वारा किया गया, जिसमें खतरों की पहचान, जोखिम नियंत्रण उपायों तथा इंडज़्शन फर्नेस इकाइयों में सुरक्षित संचालन की सर्वोज़म प्रथाओं पर विस्तृत चर्चा की गई।कार्यक्रम का संचालन सहायक प्रबंधक (एसईडी), सुश्री प्रज्ञा नाथ द्वारा किया गया।

बिजनेसमैन को जिंदा जलाने के बाद आईआईसी का ट्रांसफर

केंद्रपाड़ा ३०/१२ (संवाददाता): बढ़ते विवाद के बाद, ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले के कुडानगरि पुलिस स्टेशन के इंस्पेज़्टर-इन-चार्ज का ट्रांसफर जिला पुलिस हेडक्वार्टर कर दिया गया। यह घटना पुलिस स्टेशन से सिर्फ 300 मीटर दूर हुई, जहां कथित तौर पर एक बिजनेसमैन को जिंदा जला दिया गया था। कुडानगरि पुलिस स्टेशन के आईआईसी के पद पर तैनात अरबिंद शरण मोहंती का ट्रांसफर इलाके में एक ज़रूर हत्या के मामले में पुलिस की प्रतिक्रिया को लेकर लोगों के भारी गुस्से के बीच किया गया। नए आईआईसी ने ज्वाइन किया केंद्रपाड़ा पुलिस हेडक्वार्टर में पहले तैनात जगन्नाथ पाणिग्रही को अब कुडानगरि पुलिस स्टेशन का नया आईआईसी नियुक्त किया गया है। यह ट्रांसफर स्थानीय बिजनेसमैन सुबास मल्लिक की हत्या से जुड़े गंभीर आरोपों के बाद हुआ है। शिकायतों के अनुसार, मल्लिक को कथित तौर पर शुक्रवार देर रात उनकी दुकान के अंदर जिंदा जला दिया गया था। अपराध की गंभीरता के बावजूद, आरोप है कि स्थानीय पुलिस ने इस घटना को गंभीरता से नहीं लिया।जिस बात ने और चिंता बढ़ाई है, वह है क्राइम सीन का पुलिस स्टेशन से पास होना। कुडानगरि पुलिस स्टेशन घटना वाली जगह से सिर्फ 300 मीटर दूर है। फिर भी, आरोप है कि पुलिसकर्मियों को मौके पर पहुंचने में लगभग चार घंटे लग गए। जवाबदेही पर सवाल इस देरी ने निवासियों के बीच तीखे सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस ने इतने जघन्य अपराध पर प्रतिक्रिया देने में इतना समय ज़्यों लगाया? ज़्या आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में लापरवाही हुई? इन सवालों ने पूरे इलाके में व्यापक चर्चा छेड़ दी है। प्रशासनिक कार्रवाई इन चिंताओं को ध्यान में रखते हुए, जिला पुलिस प्रशासन ने एक सुधारात्मक प्रशासनिक उपाय के रूप में ट्रांसफर का फैसला किया है।